RNI-UPHIN/2009/30721

दिल्ली
अधिकतम तापमान 26 डिग्री
न्युनतम तापमान 14 डिग्री

एनसीआर
अधिकतम तापमान 26 डिग्री
न्युनतम तापमान 13 डिग्री

शनिवार 08 नवंबर 2025
सुर्योदय प्रातः 06 :34 बजे
सूर्यास्त सांय 17 : 31 बजे

www.khabariya.com

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज

पृष्ठ 4 गरीबी हटाओ अब हकीकत या सिर्फ चुनावी जुमला...

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित | वर्ष : 17 | अंक : 022 | गाजियाबाद, शनिवार 08 नवंबर 2025 | मूल्य : ₹ 2 | पेज : 06 | विक्रमी संवत् 2081 | युगाब्द 5126 | शाक 1946

वंदे मातरम को तोड़ने वाली विभाजनकारी सोच अभी भी देश के लिए चुनौती है: मोदी

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना शुक्रवार को कहा कि एक विभाजनकारी सोच ने 1937 में राष्ट्र निर्माण के महामंत्र वंदे मातरम के कुछ अंशों को निकालकर तोड़ दिया था और वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के भी बीज बो दिये थे।

उन्होंने देशवासियों विशेष रूप से युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि यह विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है और इससे सावधान रहने की जरूरत है।

श्री मोदी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यहां आयोजित स्मरणोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का तथा स्मारक डाक टिकट जारी किया और वंदे मातरम को समर्पित पोर्टल की भी शुरूआत की। केन्द्र सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के लिए साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की है। ये कार्यक्रम अगले एक वर्ष तक पांच चरणों में आयोजित किए जायेंगे। श्री मोदी ने आजादी से लेकर अब तक वंदे मातरम की देश निर्माण में महत्वपूर्ण यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा‘ आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से

1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को ,उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था । उसके टुकडे किये गये थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिये थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ । ये आज की पीढी को भी जानना जरूरी है क्योंकि वही विभाजनकारी सोच विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है।‘

उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सब को मिलकर इस सदी को भारत की सदी बनाना है। उन्होंने कहा,‘ यह सामर्थ्य भारत में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्ववास करना है। ‘

उन्होंने नकारात्मक सोच वाले लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी शंका पैदा करने की कोशिश को नाकाम करना होगा। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच वाले लोग शंका पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस सोच से निपटने के लिए हमें आनंदमठ के प्रकरण को ध्यान में रखकर कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा,‘ भारत माता की 140 करोड संतान और उनकी 280 करोड भुजाएं हैं । हमारे लिए कुछ भी असंभवन नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करना सबका संकल्प होना चाहिए। ‘

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर रचना एक मूल संदेश होता है,

'वंदे मातरम' गीत कांग्रेस की बैठकों का हिस्सा, आरएसएस भाजपा ने कभी नहीं स्वीकारा : खरगे

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'वंदे मातरम' गीत को राष्ट्र की सामूहिक आत्मा जागृत करने वाला स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोषक गीत बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा पर हमला किया और कहा कि राष्ट्रभक्ति का डंका पीटने वाले इस संगठन के लोगों ने अपनी शाखाओं में और बैठकों में इस गीत को कभी नहीं गया।

श्री खरगे ने वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को एक सन्देश में कहा कि इस राष्ट्रीय गीत ने हमारे राष्ट्र की सामूहिक आत्मा को जागृत किया और स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष बना रहा।

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत भारत माता अर्थात भारत के लोगों की एकता और विविधता का प्रतीक है। कांग्रेस 'वंदे मातरम्' की गौरवशाली ध्वजवाहक रही है और 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन किया था और तब इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में नयी ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य की 'फूट डालो और राज करो' नीति को समझती थी और उस समय अंग्रेजों की इस नीति के विरुद्ध 'वंदे मातरम्' अटूट शक्ति का गीत बनकर उभरा।

तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानों में देरी, यात्री परेशान

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानों में देरी, यात्री परेशान

नयी दिल्ली, 07 नवंबर (वार्ता) दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को तकनीकी समस्या के कारण पूर्वाह्न 11 बजे तक 100 से अधिक उड़ानों की रवानगी में देरी हुई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विच सिस्टम (एएमएसएस) में तकनीकी समस्या के कारण उड़ानों में देरी हो रही है। यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल डाटा को समर्थन प्रदान करता है और हवाई यातायात के स्वचालित नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एएआई ने बताया कि फिलहाल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैन्युअली फ्लाइट प्लान को प्रोसेस कर रहे हैं और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हवाई अड्डे पर सुबह से ही यह समस्या आ रही थी। कई बोर्डिंग गेट पर यात्री संबंधित एयरलाइंस के कर्मचारियों से बहस करते और परेशान दिखे। एयरपोर्ट की संचालक कंपनी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने एक बयान में बताया यात्रियों को उड़ान की अद्यतन स्थित के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी है।

कई विमान सेवा कंपनियों ने काफी देर से बोर्डिंग गेट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए जलपान की व्यवस्था की है।

आवारा कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में ले जाया जाए : न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक केंद्रों और अस्पतालों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा काटे जाने के मामलों में ''खतरनाक वृद्धि'' पर शुक्रवार को गौर करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में भेजा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में कई निर्देश पारित किए। उसने प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना एवं उनका निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। पीठ ने प्राधिकारियों को सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों आदि के परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने का निर्देश दिया ताकि कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं को रोका जा सके।

कोर्ट ने नामांकन पत्र रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार से किया इनकार

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मोहनिया सुरक्षित विधानसभा सीट के वाश्ते दाखिल अपना नामांकन पत्र खारिज किये जाने को चुनौती दी थी। सुमन के नामांकन को ''फर्जी'' जाति प्रमाणपत्र के आधार पर खारिज किया गया था। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालतें इसमें हश्तक्षेप नहीं कर सकतीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''चुनाव याचिका दायर करें।'' राजद नेता के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही और चुनाव याचिका दायर करने का जिक्र किया।

उम्मीदवार के दोषसिद्धि का खुलासा न करने पर चुनाव रद्द होगा : कोर्ट

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नामांकन पत्र में दोषसिद्धि का खुलासा न करने पर निर्वाचित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने एक पूर्व पार्षद पूनम द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। पूनम को इसलिए पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन पत्र में एक मामले में अपनी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया था। पूनम को मध्य प्रदेश के भीकनगांव नगर परिषद में पार्षद पद से हटा दिया गया था। उन्हें चेक बाउंस के एक मामले में दोषी ठहराया गया और एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही मुआवज़ा देने का निर्देश भी दिया गया था। पूनम की उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ''जब यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने अपनी पिछली दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया है, तो इससे मतदाता के स्वतंत्र निर्वाचन अधिकार के प्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है।''

प्रत्यर्पण का सामना कर रहा ब्रिटिश नागरिक दिल्ली हवाई अड्डे से भाग निकला, तलाश जारी

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी सुरक्षा चूक में, बैंकॉक से आया एक ब्रिटिश नागरिक कथित तौर पर आव्रजन क्षेत्र से भाग गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाश अभियान चलाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना 28 अक्टूबर को हुई जब फिट्ज पैट्रिक नामक ब्रिटिश नागरिक बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा। पुलिस ने बताया कि पैट्रिक को थाईलैंड के राश्ते ब्रिटेन प्रत्यर्पित किया जाना था।

संस्थागत क्षेत्रों, राजमार्गों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाए : सुप्रीम कोर्ट

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में ''खतरनाक वृद्धि'' का शुक्रवार को संज्ञान लिया और प्राधिकारियों को ऐसे कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में ले जाने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित सभी प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं और मवेशियों को हटाया जाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में कई निर्देश पारित किए। पीठ ने कहा, ''... शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों, डिपो और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए यह न्यायालय आवारा कुत्तों के प्रबंधन, जन सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझता है।''

उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने स्थानीय या नगरपालिका प्राधिकारियों के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर ऐसे संस्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया।

पीठ ने ऐसे संस्थानों के प्रशासनिक प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि परिसर में पर्याप्त बाड़, चारदीवारी, द्वारों और ऐसे अन्य संरचनात्मक उपायों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए जो आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक हों। उसने कहा कि यह कार्य जल्द से जल्द किया जाए और बेहतर होगा कि इसे आठ सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।

पीठ ने कहा कि ऐसे संस्थानों का प्रबंधन एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो परिसर के रखरखाव एवं सफाई के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें या न रहें। उसने कहा, ''उक्त अधिकारी का विवरण प्रवेश द्वार पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बारे में संबंधित नगर निकाय या प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।'' पीठ ने कहा कि स्थानीय नगर निकाय और पंचायत ऐसे सभी परिसरों का हर तीन महीने में कम से कम एक बार नियमित निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संस्थानों के भीतर या आसपास आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान न हो।

पीठ ने कहा, ''किसी भी शैक्षणिक संस्थान या अन्य संस्थानों के परिसर में पाए जाने वाले प्रत्येक आवारा कुत्ते को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार उचित बधियाकरण और टीकाकरण के बाद तुरंत एक निर्दिष्ट आश्रय स्थल में ले जाना उस नगर निकाय या प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी जिसका वह अधिकार क्षेत्र होगा।''

पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उसने कहा, ''हमने जानबूझकर ऐसे आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर न छोड़ने का निर्देश दिया है जहां से उन्हें उठाया गया हों क्योंकि ऐसा करने की अनुमति देने से ऐसे संस्थागत क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का प्रभाव ही विफल हो जाएगा।''

पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अगश्त में पारित एक आदेश का हवाला दिया जिसमें शहर की सड़कों और राजमार्गों पर आवारा पशुओं के खतरे से निपटने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करें।

महाराष्ट्र में मंत्री के बेटे को दलितों की जमीन कौड़ियों में बेची, मोदी हैं मौन : राहुल

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली मंत्री के बेटे को दलितों के लिए आरक्षित सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव बेची जाती है लेकिन श्री मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते।

उन्होंने कहा कि इस जमीन की कीमत 1800 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन राज्य सरकार के प्रभावशाली मंत्री के बेटे को कंपनी चलाने के लिए सरकार ने यह जमीन महज 300 करोड़ रुपए में बेच दी और स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट भी दे दी। आश्चर्य की बात यह है कि खुद को दलितों का हितैषी बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में मौन साध लेते हैं।

श्री गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र में दलितों के लिए आरक्षित 1800 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ़ 300 करोड़ रुपए में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई है। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी। मतलब एक तो लूट और उस पर कानूनी मुहर में भी छूट। कांग्रेस नेता ने कहा ‘ये है 'ज़मीन चोरी', उस सरकार की, जो खुद 'वोट चोरी'से बनी है। उन्हें पता है, चाहे जितना भी लूटें, वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे। न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की।‘ उन्होंने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह लुटेरों की लूट पर मौन हैं क्योंकि वे ही उनकी सरकार का आधार हैं। उन्होंने कहा ‘मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है - क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है।

बिहार में 59% से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया : एडीआर

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, बिहार में आधे से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 2023-24 के लिए अपने अनिवार्य वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने 275 ऐसे दलों की समीक्षा की – जिनमें से 184 बिहार में और 91 अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं।

रिपोर्ट के अनुसार उसने पाया कि इनमें से 163 (59.27 प्रतिशत) ने न तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की है और न ही 20,000 रुपये से अधिक के चंदा का विवरण राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों या निर्वाचन आयोग (ईसी) की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

इनमें से 113 ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार केवल 67 दलों (24.36 प्रतिशत) ने 2023-24 के लिए ऑडिट और चंदा रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें सामूहिक रूप से 85.56 करोड़ रुपये की आय, 71.49 करोड़ रुपये का व्यय और 71.73 करोड़ रुपये के चंदे दान की घोषणा की गई। दिल्ली में पंजीकृत समता पार्टी ने सबसे अधिक 53.13 करोड़ रुपये की आय की सूचना दी, उसके बाद सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) ने 9.59 करोड़ रुपये की आय की जानकारी दी।

एडीआर के आकलन में निर्वाचन आयोग की हालिया कार्रवाई को भी शामिल किया गया है, जिसमें निष्क्रियता और गैर-अनुपालन जैसे मुद्दों को लेकर अगश्त और सितंबर में 32 दलों को सूची से हटा दिया गया था।

सूची से बाहर किए गए दलों में, सबसे अधिक आय बिहार की राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी (जनवरी 2014 में पंजीकृत) ने घोषित की।

उसकी पांच साल में आय 10.66 करोड़ रुपये थी, जो 2021-22 में 4.26 करोड़ रुपये के उच्चतम श्तर पर पहुंच गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसने कोई चुनाव नहीं लड़ा।

रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पंजीकृत 28 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक उनकी संयुक्त पांच-वर्षीय आय 1.52 करोड़ रुपये है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दलों की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध थी लेकिन चंदा का विवरण नहीं था। एडीआर ने पाया कि आय और दान लगभग समान थे जो दर्शाता है कि चंदा आय का प्राथमिक स्रोत था।

देशभर में SIR के ईसी के फैसले के खिलाफ रिट पर सुनवाई 11

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

उच्चतम न्यायालय ने पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई।

गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

पीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह एसआईआर मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी।

भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

शीर्ष अदालत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रही है।

निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को ‘सटीक’ बताते हुए न्यायालय से 16 अक्टूबर को कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को केवल बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर संतुष्ट हैं।

आयोग ने न्यायालय से यह भी कहा था कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से नाम हटाने के खिलाफ किसी मतदाता ने एक भी अपील दायर नहीं की है।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने पर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम

✷ **एनसीआर टुडे. नहटौर** ✷। डिग्री कालेज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। इस अवसर पर महाविघालय के प्राचार्य डॉ. संजीव गौड़ ने राष्ट्रीय गीत के महत्व व इतिहास के बारे में छात्र - छात्राओं को संबोधित करते हुए विशतारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है, जिसका प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनन्दमठ में अन्तर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस गीत से सदियो से सुप्त भारत देश जाग उठा और आधी शताब्दी तक यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। इस उपन्यास में यह गीत भवानन्द नाम के संन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनायी थी। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड (1 मिनट और 5 सेकेंड) का समय लगता है। इस अवसर पर श्रीमती सीमा शर्मा, मोक्षपाल यादव, दुष्यन्त कुमार, यशपाल सिंह, संजीव राजपूत, पंकज शर्मा, आबिद हुसैन, विपिन सैनी, श्रीमती आराधना त्यागी, गुलअफशां आदि स्टाफ सदस्य एवं छात्र - छात्राएं उपस्थित रहें।

चार दिन पूर्व घर से लापता अधेड़ व्यक्ति का शव आम के बाग में पड़ा मिला

✷ **एनसीआर टुडे. मंडावर** ✷। थाना मंडावर कस्बे के समीप दयालवाला रोड प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास आम के बाग मे एक अधेड व्यक्ति का शव पड़ा मिला। जिसकी उम्र लगभग 60 वर्षीय जब आस पास के लोगो ने अधेड व्यक्ति का शव पडा देखा तो उसकी सूचना थाना मंडावर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया। वही शव की पहचान कुलवंत पुत्र गंभीर गांव राजारामपुर निवासी के रूप में हुई ।परिजनों ने बताया कि वह चार दिन पूर्व बिना बताए घर से कहीं चले गए थे।थाना अध्यक्ष सुमित राठी ने बताया कि शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। अगर तहरीर मिलती है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

विस्थापित लोगों के भौतिक सत्यापन को लेकर प्रमुख सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद धामपुर तथा नगीना तहसील प्रशासन से की वार्ता

✷ **एनसीआर टुडे. बिजनौर** ✷। जनपद के तहसील धामपुर और तहसील नगीना के कुछ ग्रामों में रह रहे तथाकथित विस्थापित लोगों को भौमिक अधिकार देने की पूर्व से चल रही मांग के संबंध में कल प्रमुख सचिव राजस्व महोदय श्री रणवीर प्रसाद जनपद में आए थे। उनके द्वारा कल रात्रि में जनपद के और दोनों तहसीलों के सभी अधिकारियों के साथ और सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया और आज मदपूरी ग्राम में आसपास के अन्य प्रभावित ग्रामों के ग्राम वासियों के साथ वार्ता कर समस्या को जाना गया। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी प्रभावित ग्रामों में एक विश्तृत सर्वे कर लिया जाए। शासन श्तर पर उक्त बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर निर्णय लिया जाएगा।

घर में घुसकर मारपीट के मामले में बारह के खिलाफ मुकदमा

✷ **एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा** ✷। सूरजपुर क्षेत्र के लखनावाली गांव में गुरुवार की दोपहर घर में घुसकर लाठी-डंडे से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत बारह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लखनावली गांव निवासी देव नागर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह गुरुवार की दोपहर अपने घर में बैठे थे, तभी श्यामवीर, नंदू, राजेश और कई अन्य लोग घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे और पिस्टल की बट से हमला किया। मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने पीड़ित देव नागर की शिकायत पर आरोपी श्यामवीर, राजीव उर्फ नंदू, लक्की, प्रदीप उर्फ सत्तन, राजीव अमित शर्मा और छह अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एनएमआरसी के टेक्नीशियन से मारपीट

✷ **एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा** ✷। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के एक टेक्नीशियन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित टेक्नीशियन ने एक कर्मचारी पर ड्रिल मशीन को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सूरजपुर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के रहने वाले भागचंद एनएमआरसी में टेक्नीशियन हैं। वह जैतपुर स्थित एनएमआरसी के स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं। भागचंद ने पुलिस को बताया कि एनएमआरसी में काम करने वाले रामसिम्बल ने गुरुवार को एक ड्रिल मशीन को लेकर उनके साथ मारपीट की। आरोपी ने कहा कि उन्होंने उसकी ड्रिल मशीन नहीं दी।

ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल

✷ **एनसीआर टुडे. धामपुर** ✷

नगर में दिशा इंस्टीट्यूट के पास से तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार पति-पत्नी ढाई वर्ष बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को धामपुर सीएससी में किया भर्ती।जहाँ डाक्टरों ने मासूम बालिका को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में मचा कोहराम।

मिली जानकारी के अनुसार रोहित कुमार अपनी पत्नी नीतू व पुत्री युव को लेकर अपनी ससुराल हररा ढंक्खा करमचंद जा रहा था ।जैसे ही उसकी दिशा इंस्टीट्यूट के पास पहुंची तो सामने से तेज गति से आ रहा ट्रक ने बाइक सवार को भयंकर टक्कर मार दी ।जिससे पति-पत्नी बेटी गंभीर रूप से घायल होते देख ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को धामपुर के सीएससी में किया भंरती। जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया तथा पति-पत्नी की हालत चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर बिजनौर रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लियाऔर जांच में जुट गई।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आया 8 साल के मासूम की मौत, दो महिलाए घायल

✷ **एनसीआर टुडे. बिजनौर** ✷

थाना किरतपुर क्षेत्र के ग्राम सराय इम्मा में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे आयान की मौके पर ही मौत हो गई।, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस पूरे हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है,। जिसमें ट्रैक्टर को बच्चे और महिलाओं को कुचलते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिलाओं को अस्पताल भिजवाया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर गई है।

आयुष्मान कार्ड से इलाज में कमीशन का खेल!

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सीएमओ ऑफिस तक पहुंचा भ्रष्टाचार का जाल, इलाज, कार्ड और बिल पास कराने में चल रही सांठगांठ की चर्चा

✷ **एनसीआर टुडे. बिजनौर** ✷

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जनपद बिजनौर में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कई हॉस्पिटलों में इलाज और ऑपरेशन की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि कुछ अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से किए गए इलाजों के बिल पास कराने के नाम पर सीएमओ कार्यालय के माध्यम से 10 से 15 प्रतिशत तक कमीशन की लेनदेन प्रणाली चल रही है।

सूत्रों का कहना है कि जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता, उन्हें इलाज के दौरान ही कार्ड बनवाने की सलाह दी जाती है। कई मामलों में ऐसे मरीजों से लगभग 5000 तक लेकर तत्काल आयुष्मान कार्ड बनवाने और उसी कार्ड से एक सप्ताह के भीतर ऑपरेशन तक कर देने की बातें सामने आई हैं।

जानकारी के अनुसार, इन नए बने कार्डों से इलाज कराने वाले मरीजों के बिल तेज़ी से तैयार होकर सीएमओ कार्यालय से पास भी कर दिए जाते हैं। धामपुर नगर के एक-दो हॉस्पिटलों पर भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिनकी जांच होने पर कई बड़े खुलासे संभव हैं।

विश्वसनीय सूत्रों का मानना है कि यदि जिलाधिकारी जसजीत कौर इस विषय को गंभीरता से लेकर सत्यापन कराएं, तो आयुष्मान योजना से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता है।

राजस्थान में 312 स्कूल होंगे मर्ज

राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों के तबादले की भी तैयारी

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में कम विद्यार्थियों वाले 312 स्कूलों का अगले वर्ष विलय (मर्ज) किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश में शिक्षा संसाधनों के बेहतर उपयोग और शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

मंत्री दिलावर ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2024 में 449 स्कूलों का विलय किया गया था, और अब शिक्षा विभाग ने अगले चरण के तहत 312 स्कूलों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में मिलाने की तैयारी कर ली है। इनमें 155 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 157 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है – उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 25 से कम और प्राथमिक विद्यालयों में 5 या उससे भी कम नामांकन पाए गए हैं। दो साल से लगातार नामांकन बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

दिलावर ने कहा, 'यह कदम उन इलाकों में उठाया जा रहा है जहां पास-पास कई सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से बड़े या सुविधाजनक स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इन 312 स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े। '

उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित जिलों में सर्वे की प्रक्रिया जारी है और यह कार्य अगले शैक्षणिक सत्र से पहले पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि राज्य में अब स्टाफिंग पैटर्न की नई नीति लागू की जाएगी। इस नीति के तहत 18,157 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा, 'हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी न रहे और जहां ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं, उन्हें उन स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए जहां स्टाफ की कमी है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता का जिला-वार सर्वे किया जाएगा। दिलावर ने आगे कहा कि स्टाफिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर स्कूल में एक कंप्यूटर प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इससे न केवल कंप्यूटर साइंस का पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा बल्कि स्कूलों के डिजिटल कार्य – जैसे ऑनलाइन उपस्थिति, डेटा अपडेट और अन्य ई-प्रक्रियाएं – भी बेहतर ढंग से संचालित हो सकेंगी। राजस्थान सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों को अधिक सुविधाजनक शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। हालांकि, कई ग्रामीण इलाकों में अभिभावक इस फैसले को लेकर चिंतित भी हैं।

भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे फैली गंदगी और बदबू से घटा कारोबार, अतिक्रमण भी बना समस्या

नोएडा, एजेंसी। नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे शहर का सबसे पुराना भंगेल और सलारपुर का बाजार है। एलिवेटेड रोड बनाने के बावजूद इन बाजारों की प्राधिकरण ने सुध नहीं ली। यहां फैली गंदगी, बदबू और अतिक्रमण के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों को उम्मीद है कि एलिवेडेट रोड शुरू होने के बाद उन्हें भी परेशानी से राहत मिलेगी। शहर की सबसे बड़ी मार्केट में भंगेल-सलारपुर की मार्केट शामिल है। इस मार्केट में रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। हर दिन का कारोबार भी एक करोड़ रुपये से अधिक का होता है। कारोबार के मामले में सेक्टर-27 अट्टा और सेक्टर-18 मार्केट के बाद भंगेल तीसरे नंबर की मार्केट है। बीस हजार दुकानों पर करीब 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। परंतु बाजार की मुख्य सड़क पर एलिवेटेड रोड बनाने के बाद नीचे सड़क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सड़क पर गंदगी की भरमार है। रही-सही कसर रेहड़ी-पटरी वालों ने पूरी कर दी। सड़क पर चार पहिया वाहन चालकों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। रेहड़ी-पटरी की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। व्यापारी संदीप त्यागी ने बताया कि 1980 के दशक में कुछ दुकानें शुरू हुई थीं, तब गिनती के लोग ही बाजार में खरीदारी करने आते थे। फिर 1990 के दशक में मार्केट का विस्तार होना तेजी से शुरू हो गया। ग्राहकों की बढ़ी संख्या को देखते हुए मार्केट का विस्तार होता चला गया। अब मार्केट में चार मॉल भी आ गए हैं। जिन पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रहती है। आज छोटी-बड़ी करीब बीस हजार से अधिक दुकानें है।

गन्ना किसानों के आंदोलन से घबराई कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री से लगाई मदद की गुहार

बंगलूरू, एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य में गन्ना किसानों के संकट को हल करने के लिए तुरंत बैठक की मांग की है। कर्नाटक में बीते कई दिनों से कई जिलों के गन्ना किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया हुआ है। किसान आंदोलन को समर्थन बढ़ता ही जा रहा है और यह आंदोलन कई अन्य जिलों में भी फैल सकता है। सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में अपील करते हुए लिखा कि 'मैं आपसे जल्द से जल्द बैठक करने का अनुरोध करता हूं ताकि हम अपने गन्ना किसानों, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कर्नाटक और देश में गन्ने की वैल्यू-चेन की भलाई के लिए मिलकर काम कर सकें।' सीएम बोले- एफआरपी केंद्र सरकार तय करती है कर्नाटक के गन्ना किसानों ने गन्ने के लिए 3,500 रुपये प्रति टन का मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को दखल देने का फैसला किया और शुक्रवार को किसानों और चीनी मिल मालिकों के साथ लगातार दो बैठकें बुलाईं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (स्त्रक्क) तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन और तेज न करें और शुक्रवार को बंगलूरू में बातचीत के लिए बुलाया। विहीं मिलों ने 3,200 रुपये प्रति टन से ज्यादा देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की फसल के लिए 10.25% के बेसिक रिकवरी रेट पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (स्त्रक्क) 3,550 रुपये प्रति टन तय किया है।

1800 करोड़ की सरकारी ज़मीन 300 करोड़ में बिकी

महाराष्ट्र सरकार ने उच्च-स्तरीय जाँच के दिए आदेश, अजित पवार के बेटे पार्थ पर भूमि घोटाले का आरोप

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी फर्म पर पुणे में 1,800 करोड़ रुपये के सरकारी प्लॉट को मात्र 300 करोड़ रुपये में बेचने और करोड़ों के स्टांप शुल्क की चोरी कर राज्य को राजस्व हानि पहुँचाने के आरोप की उच्च-स्तरीय जाँच शुरू की है। इस भूमि घोटाले में एक अधिकारी को निलंबित कर आपराधिक शिकायतें तैयार की जा रही हैं, जबकि अजित पवार ने मामले से खुद को अलग बताया है।

महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े कथित भूमि घोटाले की उच्च-स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा 1,800 करोड़ रुपये के संपत्ति लेनदेन में गंभीर अनियमितताओं का विवरण देने वाली एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह जाँच की जा रही है। मुंबई में अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी गई यह रिपोर्ट पुणे के मुंधवा इलाके में सरकार से जुड़ी ज़मीन की बिक्री और पंजीकरण में बड़ी खामियों की ओर इशारा करती है। इस खुलासे के बाद, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है

और एक विशेष समिति को आठ दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मुंधवा में 43 एकड़ (17.5 हेक्टेयर) का एक प्लॉट, जो 'मुंबई सरकार' के कब्जे में दर्ज था, अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को मात्र 300 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जो कथित तौर पर पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म है। ज़मीन का बाज़ार मूल्य लगभग 1,800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह ज़मीन मूल रूप से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को 15 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी, जिसे 2038 तक 50 वर्षों के लिए बढ़ाकर 1 रुपये प्रति वर्ष के मामूली किराए पर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि इस पर सरकार का स्वामित्व या हित बना रहेगा। इसके बावजूद, 272 व्यक्तियों की ओर से कार्यरत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शीतल तेजवानी और उस जगह पर डेटा सेंटर विकसित करने वाली अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के बीच सीधे तौर पर एक बिक्री विलेख पंजीकृत किया गया। 21 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क घटाकर केवल 500 रुपये कर दिया गया जांचकर्ताओं ने पाया कि घोषित सौदे का मूल्य 300 करोड़ रुपये था, जबकि करों सहित कुल देय स्टाम्प शुल्क लगभग 21 करोड़ रुपये होना चाहिए था। इसके बजाय, विलेख को केवल 500 रुपये के सांकेतिक स्टांप शुल्क पर पंजीकृत कर दिया गया। यद्यपि परियोजना डेटा सेंटर विकास के लिए 5% स्टांप शुल्क छूट के लिए योग्य थी, फिर भी स्थानीय निकाय कर और मेट्रो कर जैसे स्थानीय कर, जिनकी कुल राशि लगभग 6 करोड़ रुपये थी, लागू थे। इसलिए, पंजीकरण से राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। अंतरिम रिपोर्ट में तत्कालीन संयुक्त उप-पंजीयक रवींद्र तारू द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की पहचान की गई है, जिन्होंने आवश्यक सरकारी अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की पुष्टि किए बिना विक्रय विलेख पंजीकृत कर दिया था। तारू को आगे की जाँच तक निलंबित कर दिया गया है। 5.99 करोड़ रुपये के बकाया स्टांप शुल्क की वसूली के लिए एक सरकारी नोटिस जारी किया गया है, और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, खरीदार कंपनी और उप-पंजीयक के खिलाफ आपराधिक शिकायत तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि, हालाँकि इस लेन-देन का संबंध अमीडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के माध्यम से पार्थ पवार से जोड़ा गया है, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं है।

हरियाणा के स्कूलों में फर्जी दाखिले व मिड-डे मील घोटाले की सीबीआई जांच जल्द

फरीदाबाद, एजेंसी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिले एवं मिड-डे मील घोटाला केस में सीबीआई की टीम फरीदाबाद आकर जांच कर सकती है। सीबीआई प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिले के 10 वर्ष पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसकी जांच को लेकर सीबीआई टीम का फरीदाबाद आना भी संभव है।

सीबीआई की टीम वर्ष 2014, 15, 16 के दौरान स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों से भी बातचीत कर सकती है। बता दें कि इस मामले में स्मार्ट सिटी के 15 स्कूलों के प्रमुखों ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कार्यालय में रिकॉर्ड भी जमा कराए हैं। बता दें कि वर्ष 2013 तक रजिस्टर पर छात्रों का नाम लिखकर दाखिला होता था। इसके बाद एमआईएस पोर्टल लॉन्च

होने से छात्रों के दाखिले सहित अन्य डेटा ऑनलाइन अपलोड करना शुरू कर दिया गया। शैक्षणिक सत्र 2014-15 व 2015-16 में छात्र संख्या में भारी गिरावट आ गई। बता दें कि फरीदाबाद में 12 से 15 हजार छात्रों का अंतर आया था। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में दाखिले गिरावट आई थी। दाखिला संख्या में गिरावट आने की जांच शुरू की गई तो कई प्रदेश के कई जिलों में अवैध दाखिले और मिड-डे मील घोटाला उजागर हुआ। सीबीआई की टीम प्रदेश के कई जिलों के सरकारी स्कूलों के रिकॉर्ड भी खंगाल चुकी है। अब जांच की आंच फरीदाबाद आने वाली है।

स्कूल प्रमुखों ने ये रिकॉर्ड जमा कराए- स्कूल प्रमुखों को सत्र 2014-15 और 2015-16 के लिए सभी कक्षाओं और सेक्शनों की मूल उपस्थिति रजिस्टर। मूल प्रवेश सह निकासी रजिस्टर, जिसमें सत्र 2014-15 और 2015-16 में प्रवेश लेने वाले या स्कूल छोड़ने वालेका रिकॉर्ड हो। विभिन्न प्रोत्साहनों के वितरण का रजिस्टर जैसे छात्रवृत्ति, मासिक वजीफा, वर्दी, स्टेशनरी, बैग और भोजन का पूरा रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश दिया था।

इन स्कूलों ने जमा कराए-शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक पाठशाला सराय ख्वाजा, सेहतपुर, तिलपत, एत्मादपुर, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओल्ड फरीदाबाद, राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़खल, ऊंचा गांव और चावला कॉलोनी सहित अन्य स्कूलों के मुखिया ने रिपोर्ट जमा की है। अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी, यह मामला मेरे शिक्षा अधिकारी बनने से पहले है। इसके चलते इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। फर्जी दाखिले एवं मिड-डे मील घोटाला मामले में पूरे प्रदेश में ही जांच चल रही है। सरकार का सहयोग किया जाएगा।

एनसीआर टुडे

रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। विजय नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक घटना को तीन लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। विजय नगर सेक्टर-11 में रहने वाले आसिफ का कहना है कि बीती दो नवंबर को वह अपने किसी काम से मिलिट्री ग्राउंड से होकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह विच्छल गेट के पास पहुंचा तो वहां टेलर की दुकान पर काम करने वाले अमज व उसके भाई बाबू तथा सुहेल ने उसे रोक लिया और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित ने चार नवंबर को विजयनगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई।

सोसाइटी के गेट पर युवती से बैग छीना

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। वैभव खंड में बदमाशों ने सोसाइटी के गेट पर युवती से बैग छीन लिया। बैग में नकदी, गहने और घर की चाबियां थीं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाली शिखा खन्ना के अनुसार पांच नवंबर की शाम लगभग चार बजे वैभव खंड की जीसी सोसाइटी में रहने वाली अपनी दोश्त के घर आई थीं। सोसाइटी के गेट पर ही अचानक से एक बदमाश आया और उनके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में नकदी, जेवर और घर की चाबियां थीं। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवाश्तव ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सरकारी अस्पतालों में ओपीडी दोपहर दो बजे तक होगी

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। द्वितीय शनिवार को सरकारी दफ्तरों में बेशक अवकाश रहेगा। लेकिन सरकारी अस्पतालों में नियमित ओपीडी होगी। मरीज सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक ओपीडी में इलाज करा सकेंगे। आमतौर पर राजकीय अवकाश वाले दिन सरकारी अस्पतालों में ओपीडी केवल 12 बजे तक रहती है। जबकि पर्चे 11 बजे तक बनते हैं। एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डा.राकेश कुमार का कहना है कि शनिवार को दो बजे तक अस्पताल खुलेगा। इसके बाद गंभीर मरीज इमरजेंसी की सेवाएं ले सकते हैं।

बुजुर्ग महिला समेत डेंगू के पांच नए मरीज मिले

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। जनपद में शुक्रवार को बुजुर्ग महिला समेत डेंगू के पांच नए मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीज वसुंधरा, घूकना, राजनगर, भोजपुर, और विजयनगर के रहने वाले हैं। फिलहाल अस्पताल में चार मरीजों का इलाज चल रहा है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा 299 पर पहुंच गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. आरके गुप्ता का कहना है कि सक्रिय मरीजों के घरों के आसपास दवा का छिड़काव कराया जा रहा है।

चार्जिंग स्टेशन से 11 बैटरी चोरी

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक कंपनी के चार्जिंग स्टेशन से 11 बैटरी चोरी कर ली गईं। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कंपनी के सुपरवाइजर की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोनी में रहने वाले रवि शाह एथेलिया इंफोटेल कंपनी में सुपरवाइजर हैं। रवि के अनुसार श्याम पार्क एक्सटेंशन में कंपनी का चार्जिंग स्टेशन है। एक नवंबर को स्टेशन से 11 बैटरी ओर एक मशीन चोरी हो गई। उनके अनुसार स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की वरादात कैद हुई है। रात में दो से चार बजे के बीच एक युवक कंपनी के कर्मचारियों की ड्रेस में स्टेशन पहुंचा था। उसने कंपनी के कार्ड के जरिए गेट खोला और अंदर से 11 बैटरी और एक मशीन चोरी कर ली। रवि की तहरीर के आधार पर साहिबाबाद थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है और चोरी करने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

चौकीदार से मारपीट का विरोध करने पर चाबी से गला काटा

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चौकीदार से मारपीट का विरोध करने पर युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। युवक के गले और बाजू पर गहरे घाव हुए हैं। पीड़ित ने दो हमलावरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। मकनपुर विश्तार कॉलोनी में रहने वाले नितिन के अनुसार पांच नवंबर की रात करीब 12 बजे वह घर लौटे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि विकास चौहान और उसका साथी मनोज और एक अज्ञात युवक शराब पीकर उनके घर के सामने चौकीदार से बदतमीजी और मारपीट कर रहे थे। उन्होंने तीनों को चौकीदार से मारपीट करने से रोका तो उन्होंने ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। शोर शराबा होने पर तीनों वहा से भाग निकले। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए। उनकी गर्दन में दो टांके आए हैं। सीओ इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवाश्तव ने बताया कि विकास और मनोज ने चाबी से नितिन पर हमला किया था। मुकदमा दर्ज कर विकास और मनोज को हिरासत में ले लिया गया है।

युवती से अश्लील बातें करने के आरोपी को अग्रिम जमानत मिली

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷। युवती से अश्लील बातचीत और धमकाने के आरोपी को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने साहिबाबाद थाने में तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी से सौरभ वर्मा नामक युवक इंस्टाग्राम पर संपर्क करता था। आरोपी उस पर अश्लील हरकतें करता था और उसे आपत्तिजनक वीडियो भेजता था।

ट्रेन से कटकर युवक की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

लोनी थाना क्षेत्र स्थित खडखड़ी रेलवे हाल्ट से कुछ दूर रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार सुबह 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। युवक के दोनों पैर कटे हुए थे।

लोको पायलट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के दायें हाथ पर गुदे नाम और पते की सहायता से परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

लोनी थाना क्षेत्र स्थित खड़खड़ी रेलवे हाल्ट से कुछ दूर रेलवे ट्रैक के पास शुक्रवार सुबह एक 35 वर्षीय युवक का शव पड़ा पड़ा हुआ था। युवक के दोनों पैर कटे हुए थे। शामली से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन के लोको पायलट ने मामले की सूचना लोनी रेलवे स्टेशन अधीक्षक को दी।

स्टेशन अधीक्षक ने मामले की सूचना जीआरपी और स्थानीय पुलिस को दी। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि युवक के दायें हाथ पर नेत्रपाल सिंह पुत्र भगवत सिंह निवासी गांवडी भजनपुरा दिल्ली गुदा हुआ था।

पुलिस ने हादसे की सूचना युवक के परिजनों को दी। परिजन और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वह घर से बिना बताए निकल जाता था। इसी के चलते उसके हाथ पर नाम, पता आदि गुदवा रखा था। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम वह पड़ोस में एक समारोह में खाना खाने गया था। उसके बाद घर नहीं पहुंचा था।

परिजन ने देर रात तक उसकी तलाश की थी, लेकिन उसका पता नहीं चल सका था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह पुलिस से पुत्र के साथ हुए हादसे की जानकारी मिली। सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

प्रधान के घर और दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

वेव सिटी थानाक्षेत्र के गांव दीनानाथपुर पूठी में गुरुवार रात ग्राम प्रधान के घर और दफ्तर पर फायरिंग कर दी। थार और बाइक से आए हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। वीरेंद्र यादव ग्राम पंचायत दीनानाथपुर पूठी गांव के प्रधान हैं। उनके बेटे अनुज यादव ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10 बजे वह घर के गेट पर खड़े थे।

तभी गांव के ही नरेंद्र और सुनील और गांव का ही पवन यादव थार गाड़ी और बाइक पर सवार होकर पहुंचे। आरोपियों ने रिवाल्वर और बंदूक से उन पर फायरिंग कर दी। अनुज ने भागकर जान बचाई। हमलावरों के जाने के बाद उन्होंने पड़ोसी के घर जाकर डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

अनुज का कहना है कि घर पर फायरिंग के बाद आरोपी गांव स्थित पिता के दफ्तर पर पहुंच गए। वहां नरेंद्र ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की। चुनावी रंजिश में वारदात करने का आरोप अनुज का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र से चुनावी रंजिश चल रही है। बीते साल कोर्ट परिसर में भी ब्लॉक प्रमुख ने जान से मारने की धमकी दी थी।

इस संबंध में अनुज के भाई मनोज ने कविनगर थाने में शिकायत दी। इसमें 12 मार्च 2024 की दोपहर 2.10 बजे गाजियाबाद कचहरी में सुनील यादव, पवन और लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया था। उसी दिन जितेंद्र यादव ने उनके पिता विरेंद्र यादव और सुनील यादव को फोन पर धमकी दी। पुलिस ने दो अप्रैल 2024 को जितेंद्र यादव और उसके भाई सुनील यादव के अलावा पवन के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पूर्व में शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप अनुज का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों से कई बार शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार रात हुई घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। अनुज यादव ने वेव सिटी थाने में शिकायत दी है।

सीओ वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि शिकायत के आधार पर तीन नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना में लाइसेंसी असलहा के इश्तेमाल मिलने पर शस्त्र लाइसेंस निरश्त कराने की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

लंबे कद को लेकर अभद्र टिप्पणी का विरोध करने पर युवक से मारपीट

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रामस्वरूप कॉलोनी शहीद नगर में एक युवक ने लंबे कद को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई।

गंभीर रूप से घायल युवक को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। मामले में युवक के पिता की ओर से चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामस्वरूप कॉलोनी शहीद नगर में रहने वाले लोकेश कुमार के अनुसार उनका बेटा रोहित उर्फ यश पांच नवंबर की रात लगभग दस बजे घर के पास की दुकान से कुछ सामान लेने गया था। इस दौरान वहां अनस, फरमान, शोएब और अजहर ने रोहित के लंबे कद को लेकर अभद्र टिप्पणी की। जिसका रोहित ने विरोध किया तो चारों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। रोहित को गंभीर रूप से घायल करने के बाद चारों वहां से फरार हो गए। रोहित किसी तरह घर लौटा तो वह उसे अस्पताल ले गए।

जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रोहित को वापस घर भेज दिया गया। अलग दिन रोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिलहाल वह निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। लोकेश की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

होटलकर्मी से मारपीट कर स्कूटी छीनी

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

टीला मोड़ थाना क्षेत्र में अज्ञात युवकों ने एक युवक से मारपीट करके स्कूटी

चोरी कर ली। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

बागपत में रहने वाले दलीप के अनुसार वह दिल्ली के लीला होटल में कार्मचारी हैं। तीन नवंबर की सुबह वह घर से ड्यूटी पर जा रहे थे। इस दौरान लोनी-भौपुरा रोड पर टीवीएस शोरूम के सामने गलत दिशा से आ रहे एक बुजुर्ग ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों गिर गए। इस दौरान वहां दो बाइक पर सवार चार युवक आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। जान बचाने के लिए वह मौके से भाग गए। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो वहां उनकी स्कूटी नहीं थी। दलीप का आरोप है कि हमलावरों ने उनकी स्कूटी छीनने के लिए ही उनके साथ मारपीट की थी।

सीओ शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के अनुसार पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

रोडरेज में छत से पत्थर बरसाए, चार लोग घायल

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र के जाग्रति विहार में गुरुवार देर शाम रोडरेज को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने पथराव कर दहशत फैला दी।

पथराव में दंपती समेत चार लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बाइक से टक्कर मारने का आरोप भी लगाया है। पुलिस का कहना है कि के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। गुलधर सैकेंड के जाग्रति विहार निवासी बृजमोहन शर्मा का कहना है कि छह नवंबर को वह अपने घर लौट रहे थे। जब वह गली में पहुंचे तो वहां कुछ लड़के और लड़कियां आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे।

उन्होंने राश्ता खाली करने के लिए कहा तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। कहासुनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। बृजमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान सचिन, इकांश, मनी और रितु तथा सानिया नाम की लड़की ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि शोर-शराबा सुनकर पत्नी और दो किरायेदार बीच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने छत से पथराव कर दिया और एक युवक ने बाइक से उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गिरकर घायल हो गए।

सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। घटना के संबंध में पीड़ित ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दी। सीओ कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल पाकर 200 लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

नगर जोन की पुलिस ने चोरी, लूट और गुम हुए 200 मोबाइल बरामद किए हैं। शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में एसपी नगर ने पीड़ितों को मोबाइल हाथ में दिए तो उनके चेहरे खिल उठे। डीसीपी के मुताबिक बरामद हुए मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है।

इन मोबाइलों के खरीदारों से लुटेरों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। डीसीपी नगर धवल जयसवाल ने बताया कि थानों पर रोजाना मोबाइल गुम होने, स्नैच और लूटे जाने की शिकायत आती हैं। ऐसे मोबाइल को ट्रेस करने के लिए पुलिस की सर्विलांस टीम निरंतर प्रयासरत रहती हैं।

नगर जोन पुलिस द्वारा सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) द्वारा गुम हुए मोबाइलों की तलाश की गई और 200 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद कर लिए गए।

डीसीपी ने बताया कि बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। यह मोबाइल दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल के स्वामियों को पुलिस लाइन बुलाकर उन्हें मोबाइल सुपुर्द किए गए। वहीं, पीड़ितों का कहना है कि वह अपने गुम और लूटे गए मोबाइल को मिलने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस ने नई तकनीकी के जरिए हमारे मोबाइल खोजकर वापस कर दिए, यह उनके लिए खुशी की बात है।

एसपी नगर ने बताया कि लूट और चोरी के मोबाइल खरीदने वालों से पूछताछ के आधार पर मोबाइल लुटेरों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली और विजयनगर पुलिस ने सर्वाधिक मोबाइल बरामद किए नगर जोन में सर्वाधिक मोबाइल बरामद करने के मामले में नगर कोतवाली और विजयनगर थाना पुलिस सबसे आगे रही। दोनों थानों की पुलिस ने 50-50 मोबाइल फोन बरामद किए। नंदग्राम थाना पुलिस ने 28, मधुबन बापूधाम और कविनगर पुलिस ने 24-24 मोबाइल, सिहानी गेट पुलिस ने 16 मोबाइल तथा साइबर थाना पुलिस ने आठ मोबाइल बरामद किए हैं।

ऑनलाइन गेम के चक्कर में युवती ने सवा लाख गंवाए

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

विजयनगर थानाक्षेत्र में रहने वाली एक युवती के साथ ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लूडो गेम ऐप डाउनलोड करने के कुछ दिनों बाद ही उसके बैंक खाते से 1.21 लाख रुपये की रकम गायब हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विजयनगर सेक्टर नौ में रोज बेल पब्लिक स्कूल के पास रहने वाली सोनी भारद्वाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन में लूडो गेम ऐप डाउनलोड किया था। वह कुछ दिन तक इस गेम को खेलती रहीं।

इसके बाद 17 अगश्त 2025 को उनके एक्सिस बैंक के खाते से अचानक 1.21 लाख रुपए कट गए। पीड़िता ने बताया कि उन्हें इस ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी नहीं थी। खाते से रकम कटने की सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत बैंक से संपर्क किया और उसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना के संबंध में रोजी भारद्वाज ने पांच नवंबर को विजयनगर थाने में शिकायत देखकर कार्रवाई की गुहार लगाई।

सीओ कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। विजयनगर थाने की साइबर सेल द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सीओ ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी अज्ञात या अविश्वसनीय ऐप को मोबाइल में डाउनलोड न करें और बैंकिंग विवरण साझा करने से बचें।

ऑनलाइन गेमिंग या मनोरंजन ऐप के माध्यम से बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है।

ग्राम मलकपुर में दबंगों ने घर में घुसकर महिला व बुजुर्ग पर किया हमला, जान से मारने की धमकी

✷ एनसीआर टुडे. बिजनौर ✷

थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम मलकपुर में एक विधवा महिला के घर में दबंगों द्वारा जबरन घुसकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है। आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक जो शराब और नशे के आदी बताए जा रहे हैं, अक्सर उसे और उसके परिवार को परेशान करते रहे हैं।

पीड़िता का कहना है कि दिनांक 3 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे उक्त आरोपी उसके घर में घुस आए। उस समय पीड़िता की माँ और भाभी घर में मौजूद थीं। आरोप है कि दबंगों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी और पीड़िता की माँ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, यहां तक कि गला दबाने का भी प्रयास किया।

मारपीट के दौरान घर में रखे सामान को भी क्षतिग्रश्त करने का आरोप है। साथ ही सोने-चांदी के कुछ जेवर ले जाने की भी बात कही गई है। शोर सुनकर पास के लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपितों से उसे और उसकी माँ को लगातार जान का खतरा बना हुआ है। उसने पुलिस से सुरक्षा और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना स्योहारा पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शेरकोट में चोरी की मोटरसाइकिल सहित अभियुक्त गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. बिजनौर ✷

थाना शेरकोट पुलिस ने तत्परता व सतर्कता का परिचय देते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सराहना का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 05 नवम्बर 2025 को वादी सतीश कुमार पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना शेरकोट ने थाना शेरकोट में तहरीर दी थी। उसकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है।

इस प्रकरण में थाना शेरकोट पर मुकदमा मु0अ0सं0 183/2025 धारा 303(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था।विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए अभियुक्त मनीष कुमार उर्फ मंगल सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला बीरथला, कस्बा व थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को चिन्हित कर लिया। तत्पश्चात आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को अभियुक्त को चोरी की गई मोटरसाइकिल सहित-गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ०नि० विपिन कुमार, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, अंकुर कुमार शामिल रहे।

बुजुर्ग की मौत के मामले में अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज

✷ एनसीआर टुडे. नोएडा ✷

थाना दनकौर क्षेत्र में स्थित निम्स अस्पताल में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गिरकर हुई मौत के मामले में उसके बेटे ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को मामला दर्ज कराया।

थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शकील पुत्र शाहिद ने आज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 31 अक्टूबर को कस्बा जेवर में निम्स अस्पताल द्वारा एक कैंप लगाया गया था जहां उसने अपने पिता शाहिद (85 वर्ष) व अपनी मां चमन को दिखाया।

शकील ने कहा है कि डॉक्टर के कहने पर उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिकी में शकील ने आरोप लगाया है कि चार नवंबर को उसके पिता वार्ड से गायब हो गए।

उसकी मम्मी के अलावा वहां उपचार करा रहे अन्य लोगों ने उसे यह सूचना दी।

शकील का कहना है कि जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसके पिता नहीं मिले। इसके बाद उसने पांच नवंबर को थाना दनकौर में अपने पिता की गुमशुदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस उसके पिता की तलाश कर रही थी।

कार से रेकी कर घरों में चोरी करने वाले गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. नोएडा ✷

सेक्टर-24 थाने की पुलिस ने कार से रेकी करने के बाद बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के सरगना समेत तीन बदमाशों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में एक सुनार भी शामिल है।

आरोपियों की निशानदेही पर एक कार, सोने के गहने, महंगी घड़ियां और चाकू समेत अन्य सामान बरामद हुआ। एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि दो सप्ताह पहले थाना क्षेत्र में एक ही दिन में चोरी की दो वारदातें हुई थीं। जांच में शक हुआ कि एक ही गिरोह ने दोनों जगह वारदातें कीं। कुछ समय बाद घटना का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो भी सामने आ गया। इसमें बदमाश वारदात करते दिख रहे थे।

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। गिरोह के बदमाश शुक्रवार को कार से फिर वारदात करने के लिए आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय मिली फुटेज से कार सवार दोनों बदमाशों के चेहरों का मिलान किया गया। इसके बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। बदमाशों के बताए अनुसार सुनार को भी दबोच लिया गया। आरोपियों की पहचान बुलंदशहर के डिवाई निवासी गोपाल और दिल्ली के कल्याणपुरी निवासी पप्पू उर्फ रामजी और मुकेश उर्फ टीटू के रूप में हुई। मुकेश सुनार है। पप्पू की उम्र 55 साल है। गोपाल की उम्र 39 और मुकेश की 46 साल है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्त में आए आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं।

आरोपियों ने नोएडा के अलावा दिल्ली समेत अन्य जगहों पर भी चोरी की हैं। पूर्व में दोनों मुख्य आरोपी दिल्ली से जेल जा चुके हैं। बदमाशों ने दिल्ली में 20 से अधिक वारदात की हैं। दोनों की तलाश दिल्ली पुलिस भी कर रही थी। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपने कई अन्य साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पुलिस अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। नंबर प्लेट बदल करते थे वारदात पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया कि जब उन्हें वारदात करनी होती थी तो कार की नंबर प्लेट बदल देते थे। रेकी करने के दौरान अगर कोई टोकता तो आरोपी किराये का कमरा तलाश करने की बात कहकर बच निकलते थे।

जहां वारदात करनी होती थी, वहां से 100 मीटर की दूरी पर ही बदमाश अपनी कार खड़ी कर देते थे। आरोपी झोला या बैग अपने पास रखते थे। चोरी के सामान को बदमाश झोले में रखकर फरार हो जाते थे। किसी भी घर का ताला तोड़ने के लिए बदमाश महज एक से दो मिनट का समय लेते थे। सुनार नौवीं कक्षा फेल सुनार मुकेश नौवी फेल है। पप्पू और गोपाल ने छठवीं तक की पढ़ाई की हुई है। मुकेश दोनों से चोरी के गहने कम दाम में खरीदता था। वारदात के बाद जैसे ही दोनों बदमाश सुनार को गहने देते थे, वह तुरंत उसे पिघलाकर आकार बदल देता था। बदमाशों ने पूछताछ के दौरान यह भी बताया कि अगर कोई चोरी का विरोध करता था तो उसे डराने के लिए वह अपने पास चाकू रखते थे। दोनों के खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में दस से अधिक केस दर्ज हैं।

संपादकीय

बिहार में सूखा तो यूपी में बहार है

एक दौर में नीतीश कुमार देश भर में शराबबंदी की बात करते थे। उनके महिला समर्थन के मिथ में शराबबंदी को भी कारण माना जाता है लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं है। इस सवाल पर एनडीए में उनकी साझीदार भाजपा और अन्य दल भी चुप्पी ही साधे हुए हैं। एनडीए के छोटे दलों की छोड़ भी दें तो भाजपा की चुप्पी के पीछे काफी बड़े कारण है।

बिहार जाना हो तो सावधान होकर जाइए। बार्डर आते ही आपकी ऐसी तलाशी शुरू होगी कि आप सचमुच में अपमानित महसूस करेंगे। और यह तलाशी भी एक जगह नहीं या एक बार न होकर बार-बार होगी। चुनाव है तो यह अभियान बढ़ा है वरना वैसे भी राज्य पुलिस का यह प्रिय काम बन गया है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है।

चुनाव में भी सौ करोड़ से ज्यादा की जो धर-पकड़ हुई है उसमें शराब और ड्रग्स का हिस्सा अस्सी फीसदी से ज्यादा है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। वहां नकदी जब्त होने का हिस्सा ज्यादा हुआ करता है और यह तब है जबकि बिहार चुनाव में कोई भी दल शराबबंदी का मुद्दा नहीं बना रहा है। शुरू में प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठाया रहे थे लेकिन लोगों में इसका असर खास न देखकर चुप्पी सी साध ली है। वह नीतीश कुमार और जदयू भी इसे नहीं उठा रहे हैं जो इसे ले आये हैं। एक दौर में नीतीश कुमार देश भर में शराबबंदी की बात करते थे। उनके महिला समर्थन के मिथ में शराबबंदी को भी कारण माना जाता है लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं है। इस सवाल पर एनडीए में उनकी साझीदार भाजपा और अन्य दल भी चुप्पी ही साधे हुए हैं।

एनडीए के छोटे दलों की छोड़ भी दें तो भाजपा की चुप्पी के पीछे काफी बड़े कारण है। आज यह सिर्फ मुल्क में ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में शासन कर रही है। शराब ही आज राज्यों की आमदनी का मुख्य स्रोत है और उस पर प्रतिबंध या उसके करों में कमी-बेसी करना पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के फैसलों की आलोचना तो आत्मघाती होगी ही, तारीफ भी मुश्किल है। ऐसी हालत में हर जगह उसकी सरकारों को जवाब देना मुश्किल होगा।

उसके लोग भी मानते हैं कि शराबबंदी से बिहार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है तो साथ ही वहां शराब की बिक्री का एक पूरा अवैध नेटवर्क बन गया है और वह हर कहीं शराब उपलब्ध करा देता है। नकली शराब बनाने का धंधा भी चल रहा है। और भाजपा समेत काफी सारे दलों का मानना है कि यह नेटवर्क राजद से जुड़े लोग चलाते हैं। कई बार यह आरोप भी लगता है कि बिहार पुलिस बाकी धंधे छोड़कर शराब पकड़ने और उस बहाने कमाई करने में लगी रहती है। इस चक्कर में पुलिस की सामान्य जिम्मेदारियों का निर्वहन भी ठीक से नहीं होता।

बिहार की शराबबंदी से अगर पुलिस वालों का कु छ लाभ-घाटा होगा तो उसके सीमावर्ती प्रदेशों को भी लाभ है और सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेपाल और झारखंड का नंबर भी है लेकिन शराब की तस्करी में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर होगा। पकड़ी गई शराब में उसकी सीमा पर जब्त माल का आकार-प्रकार भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अति व्यावहारिक और 'लाभदायी शराब नीति ने जिस तरह से राज्य में शराब की खपत और साथ ही सरकार के खजाने में वृद्धि की है वह चौंकाने वाला है।

पिछले वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश को शराब की बिक्री से 51000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला जो कि राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है। और भले ही शराब पीने के मामले में उत्तर प्रदेश वाले अभी पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों और दक्षिण के राज्यों से पीछे हों पर वे जल्दी ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे मानस में पंजाब ही सबसे ज्यादा शराब खपत करने वाला है लेकिन वास्तविकता में अब वह तेलंगाना के आधे में रह गया है।

उत्तर प्रदेश के बारे में भविष्यवाणी करने का आधार उसकी नई शराब नीलामी नीति की व्यावहारिकता, नीतियों में निरन्तरता और शराब के व्यापारियों द्वारा इसे पसंद करना कारण है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान के लिए आप आनलाइन नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं और इस चलते कीमतों में घालमेल की गुंजाइश एकदम कम हो गई है।

ऊपर से नीतियों में स्थिरता ने बाहर से आकार प्रदेश में कारोबार करने वालों को निश्चिंत कर दिया है। अब यह सवाल मत उठाइएगा कि एक संन्यासी मुख्यमंत्री यह सब कैसे कर लेते हैं। असल में यह काम नौकरशाही का है और उन्होंने ही बियर और देसी के साथ विदेशी शराब बेचने की दुकानें चलाने की अति-लाभदायक नीति बनाई है। अब इससे प्रदेश के लोगों का क्या लाभ है वह भले विवादास्पद हो लेकिन उससे कोविड पूर्व का 24 हजार करोड़ का राजस्व 51 हजार करोड़ पार कर गया है जो नई शराब नीति डेढ़ साल पहले आई है।

उसमें शराब और गांजा-भांग की सभी चार तरह की दूकानों के लिए आनलाइन नीलामी और लाटरी की व्यवस्था हो गई है। और पहली ही नीलामी में न सिर्फ चार लाख से ज्यादा आवेदक आये बल्कि 27 हजार से ज्यादा दुकानें नए मालिकों के हवाले हो गईं। प्रोसेसिंग फीस के रूप में ही 2000 करोड़ की कमाई हो गई और देश भर में इस नई नीति की व्यावहारिकता का डंका बजने लगा।

इस व्यावहारिकता में बिहार से लगे कस्बों और शहरों में दुकानों की बाढ़ और उनसे मोटा राजस्व पाना भी एक सफलता थी। कुशीनगर जिले के तमकुहीराज जैसे छोटे कस्बे में जब सिद्धार्थनगर में कारोबार करने वाले व्यवसायी को दुकान मिल गई तो वह यह देखकर हैरान था की पुराने शहर में अद्धा-पौवा और बोतल खरीदने वाले थे तो यहां एक साथ कई-कई बोतल। बिहार में आती-जाती गाड़ियां अकसर बार्डर के इन ठिकानों पर रुककर माल उठाती हैं। गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली, बलिया, देवरिया और सोनभद्र जिलों को भी इसी के चलते ज्यादा राजस्व मिलना शुरू हुआ।

ऐसा ही लाभदायक फैसला सिर्फ बियर या आईएफएमएल अर्थात कंट्री मेड फ़ारेन लिकर की दूकानों को बंद करके कम्पोजिट दुकान खोलने का भी था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही करीब दस हजार कम्पोजिट दुकानें खोली गईं। कहना न होगा कि ये दोनों राज्य भाजपा शासित है और भाजपा एक तरफ तो उनसे यह सीख लेती है लेकिन बिहार की सीख कहीं भी लागू करने का प्रयास नहीं करती।

गरीबी हटाओ अब हकीकत या सिर्फ चुनावी जुमला...

मनोज कुमार अग्रवाल

साठ साल तक गरीबी हटाओ सिर्फ एक चुनावी जुमला रहा जिसे खूब उछाला गया लेकिन नतीजा ठेंगा निकला लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद गरीबी हटाओ सिर्फ लोक लुभावन नारा नहीं है ऐसा खुद विश्वबैंक मानता है।

पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो प्रगति की है, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में मात्र 5.3 प्रतिशत रह गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लगभग 26.9 करोड़ भारतीय इस अवधि में अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल सके हैं। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब वैश्विक स्तर पर महामारी, आर्थिक मंदी और युद्ध जैसे संकटों ने विकासशील देशों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं।

विश्व बैंक के मुताबिक, 2011-12 में देश में लगभग 34.4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, जिनकी संख्या अब घटकर मात्र 7.5 करोड़ रह गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ही यह दावा कि सरकार ने 2.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। इसी कड़ी में केरल ने खुद को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित कर दिया है।

कुछ अतिशयोक्ति भले लगे, लेकिन समग्र रूप से देखें तो भारत ने गरीबी घटाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। फिर भी सवाल उठता है, क्या गरीबी में यह गिरावट समान रूप से सभी वर्गों तक पहुंची है? हाल ही में आई जी 20 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटी ऑन ग्लोबल इनइम्क्वैलिटी की रिपोर्ट इस सवाल का स्पष्ट उत्तर देती है कि नहीं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2000 से 2023 के बीच शीर्ष 1 प्रतिशत अमीरों की संपत्ति में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तुलना करें तो चीन में यह वृद्धि 54 प्रतिशत रही। यह आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नहीं बंटा, जबकि शीर्ष वर्ग की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई, देश की निचली आधी आबादी के पास अब भी संपत्ति का नगण्य हिस्सा है। यह आंकड़ा न केवल आर्थिक विषमता की भयावहता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि विकास के लाभसमान से सीमित वर्ग तक सिमट गए हैं।

पिछले दो दशकों में भारत ने जीडीपी वृद्धि, तकनीकी नवाचार और वैश्विक निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन इन उपलब्धियों की कीमत सामाजिक और आर्थिक विषमता के रूप में चुकानी पड़ी है। शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों ने जहां 62 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह आंकड़ा बताता है कि विकास की गति भले ही तेज रही हो, लेकिन उसका वितरण बेहद असमान रहा है। ग्रामीण भारत में आज भी लाखों परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पोषण जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।

शहरों की चमकदार ऊंचाइयों के बीच गांवों की दरिद्रता एक सच्चाई बनकर सामने आती है। यह असमानता केवल आय की नहीं, बल्कि अवसरों, संसाधनों और सामाजिक सम्मान की भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों ने 2000 से 2024 के बीच नई संपत्ति का 41 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया है, जबकि दुनिया की निचली आधी आबादी को केवल 1 प्रतिशत मिला। यह अनुपात किसी भी दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है।

यह स्थिति लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु कार्रवाई, तीनों के लिए खतरा है। जब

संपत्ति कुछ हाथों में सिमट जाती है, तो राजनीतिक शक्ति भी उन्हीं हाथों में केंद्रित होने लगती है। इससे नीति निर्माण पर कॉर्पोरेट और संपन्न वर्गों का प्रभाव बढ़ता है, और जनहित पीछे छूट जाता है। दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्राजील जैसे देशों में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट है, जहां ऐतिहासिक रूप से असमानता की जड़ें गहरी रही हैं।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि जिन देशों में असमानता अधिक है, वहां लोकतांत्रिक पतन की संभावना सात गुना अधिक होती है, यानी आर्थिक विषमता अब केवल सामाजिक या नैतिक समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता की जड़ बन चुकी है। जब समाज में असमानता बढ़ती है, तो उसका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की आधी आबादी अभी भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। लगभग 1.3 अरब लोग अपनी जेब से स्वास्थ्य खर्च करने के कारण गरीबी में जी रहे हैं। इसके अलावा, 2.3 अरब लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, यह संख्या 2019 की तुलना में 33.5 करोड़ अधिक है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बावजूद भूख, बीमारी और बेरोजगारी में वाश्तविक सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि अत्यधिक असमानता कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानव निर्मित परिणाम है और इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति से बदला जा सकता है। जब तक नौति निर्माण का केंद्र मानव विकास नहीं चनेगा, तब तक आर्थिक विकास केवल आंकड़ों में सीमित रहेगा। कराधान नीति, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश, तथा श्रम बाजार में सुधार जैसे कदम असमानता को घटाने में मदद कर सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, वहां समान अवसर की गारंटी सबसे बड़ी नीति प्राथमिकता होनी चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की गरीची घटने की कहानी प्रेरक है, लेकिन यह अधूरी है यदि इसके साथ असमानता का पैमाना ऊंचा जाता रहे। आर्थिक विकास का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन मिले। अमीरों की संपत्ति का बढ़ना बुरा नहीं, लेकिन जब गरीबों की हिस्सेदारी घटती जाती है, तो विकास की दिशा पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है।

अब समय आ गया है कि हम जीडीपी के आंकड़ों से आगे बढ़कर मानव विकास सूचकांक और समानता सूचकांक को विकास का पैमाना बनाएं। क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है चरम असमानता एक चुनाव है, भाग्य नहीं। भारत को अब यह तय करना है कि वह इस चुनाव में किस ओर खड़ा होना चाहता है अमीरी की चमक के साथ बढ़ती गरीबी की छाया में, या संतुलित विकास के उजाले में। भारत की प्रगति तभी सार्थक होगी जब विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वह शहर की गगनचुंबी इमारतों में रहने वाला नागरिक हो या गांव की मिट्टी में पसीना बहाने वाला किसान।

राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति सुधार और सामाजिक संवेदना ये तीन श्तंभ हैं जिन पर समानता आधारित विकास टिक सकता है। असमानता को कम करना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और मानव गरिमा की रक्षा का अनिवार्य उपाय है।

सरकार को उसके प्रयासों के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए तथापि अभी बहुत काम करना बाकी है खासकर जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देना चाहिए ताकि संसाधनों का निरंतर विकास और आबादी में संतुलन व सामंजस्य बनाया जा सके।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

गुम होते आदिवासियों के वैधानिक अधिकार

सुधीर पाल

कानून की जिस जमीन को आप सख्त समझ रहे हैं, उसकी मिट्टी भहरा रही है। आपके पैरों तले जमीन खोखली हो गयी है। संवैधानिक और वैधानिक ढांचे के भीतर आदिवासियों को भूमि, वन और आजीविका के विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। पांचवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विश्तार) अधिनियम 1996 (पेसा), वन अधिकार कानून 2006 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 आदिवासियों के विशिष्ट अधिकारों को मान्यता देते हैं। लेकिन पिछले पाँच वर्षों में संसाधन प्रबंधन से जुड़े क़ानूनों को "व्यापार की सुगमता" के नाम पर बदल दिया गया है। यह आदिवासियों के विशिष्ट संवैधानिक अधिकारों को गायब कर देने की सुनियोजित प्रक्रिया है। हालिया कानूनी सुधारों ने संसाधन प्रबंधन की दिशा को कॉरपोरेट फ़्रेंडली बना दिया है।

2019 के बाद से केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय, खनन और भूमि संबंधी आधे दर्ज़न क़ानूनों में तेजी से संशोधन किया। संशोधन का उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और अनुमति प्रक्रियाओं को सरल करना बताया गया। परंतु इसके पीछे का उद्देश्य वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को और मज़बूत करना रहा।

नई दिल्ली स्थित आदिवासी अधिकारों की जन वकालत करने वाली संस्था लीगल रिसोर्स सेंटर ने आदिवासियों और वनाश्रित समुदायों के जीवन और संघर्ष को प्रभावित करने वाले कानूनों में आए बदलावों का अध्ययन किया है। अध्ययन बताते हैं कि हाल के कानूनी सुधार से आदिवासी अधिकारों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगश्त 2023 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया गया। कुछ छोटे वन अपराधों के लिए कारावास की सज़ा समाप्त कर दी गयी और इसकी जगह आर्थिक जुर्माना का प्रावधान किया गया। वन अपराधों से होने वाली हानि की भरपाई के लिए सामूहिक दंड जैसे खतरनाक प्रावधान जोड़े गये हैं। वन अधिकारियों के अधिकार बढ़ा दिए गये हैं। जुर्माना लगाने और उसकी वसूली के लिए वन अधिकारी को सक्षम घोषित किया गया है। लीगल रिसोर्स सेंटर की संस्थापक और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील सोमन्ना खन्ना बताती हैं कि खनन परियोजनाओं और वन भूमि के परिवर्तन (फॉरेस्ट डायवर्ज़न) में तेज़ी आई है। 2020 और 2021 में व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए वन और पर्यावरण स्वीकृतियों के सारे रिकार्ड तोड़ दिए गये।

रिकॉर्ड श्तर पर वन भूमि का डायवर्ज़न

लीगल रिसोर्स सेंटर की रिपोर्ट 'राज्य के एजेंडे का रहस्य' में बताया गया कि 23 मार्च 2020 के पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 का मसौदा नागरिक संगठनों के भारी विरोध और कर्नाटक तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के हश्तक्षेप की वजह से स्थगित हो गया। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके कई प्रावधानों को विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के माध्यम से लागू कर दिया है।

जन सुनवाई से संबंधित प्रावधानों को कमजोर करना एवं ईआईए प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन को कमजोर करना था। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) की प्रक्रिया को भी छोटा कर दिया गया। परियोजनाओं को एक्सप्रेस क्लीयरेंस की श्रेणी देने का प्रावधान किया गया। इन अनुमतियों में खनन, बांध, सड़क, रेल और औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ शामिल थीं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2018–2023 के बीच लगभग 6, 68, 400 हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ।

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, यह संख्या ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2020 और 2021 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए जो अनुमतियाँ दीं, वे पिछले दशकों का रिकॉर्ड तोड़ श्तर थीं। एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार भारत में 2021–23 के बीच लगभग 4, 380 वर्ग किलोमीटर (4, 38, 000 हेक्टेयर) की वृक्ष-आच्छादन वाली भूमि खो गई, जिसका अधिकांश हिस्सा प्राकृतिक वन था (94 %)।

कई अनुमति प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीकृत कर दिया गया। इससे स्थानीय ग्राम सभाओं की भागीदारी लगभग समाप्त हो गई। वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग पर निर्णय लेने में अब आदिवासी समुदायों की सहमति केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।

वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन

सबसे प्रमुख बदलाव, अगश्त 2023 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में हुआ संशोधन है। इसे अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 कहा गया। संशोधन में एक्ट की प्रकृति बदल दी गई है। अब यह कानून केवल उन भूमि-खण्डों पर लागू होगा जो 1927 के वन अधिनियम या अन्य कानून के तहत घोषित/सूचित वनभूमि हों या 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हों। इसमें उन वन भूमियों को कानून से बाहर रखा गया जो अधिसूचित नहीं थीं या 1980 से पहले रिकार्ड में दर्ज नहीं थीं लेकिन आज भी वन-स्वरूप में हैं। वन संरक्षण अधिनियम के दायरे को सीमित कर दिया गया है। भूमि और वन भूमि तथा कुछ गतिविधियों को केंद्र सरकार से वन परिवर्तन मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है।

वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के दायरे में कई नए प्रकल्प जोड़े गए हैं- जैसे रेलवे लाइनों और सड़कों के नजदीक गैर-वन गतिविधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 100 किलोमीटर तक महत्वपूर्ण रैखिक आधारभूतन संरचना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा-संबंधित संरचना, निजी चिड़ियाघर और सफारी, इको-टूरिज्म, संपर्क लाइनों के जनहित कार्य आदि। संसद के स्थान पर केंद्र सरकार को दिशा निर्देश आदि की शक्ति प्रदान की गई।

अब सैद्धांतिक वन स्वीकृति (स्टेज-1) की वैधता 2 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। केंद्र सरकार यह तय कर सकती है कि विभिन्न रैखिक आधारभूत परियोजनाओं में अंतिम वन स्वीकृति (चरण-2) मिलने से पहले किन कार्यों को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। रक्षा, रणनीतिक, राष्ट्रीय महत्व, सार्वजनिक हित और आपातकालीन परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से ऑफ़लाइन आवेदन की व्यवस्था की गई।

एमएमडीआर की प्राथमिक अनुसूची के भाग-डी और सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए प्रतिपूरक वनरोपण में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई। प्रतिपूरक वनरोपण भूमि को अब वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा या प्रासंगिक वन कानून के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

बदलाव की यह प्रक्रिया सीधे-सीधे आदिवासी और वन-निवासी समुदायों के अधिकारों पर असर डालती है। गैर अधिसूचित वन-भूमियों को अब कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है। इससे वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार तथा ग्राम सभा-आधारित वन प्रबंधन कमजोर की प्रक्रिया कमजोर हुई है।

सोमन्ना खन्ना कहती हैं कि इससे न केवल वन क़ानूनों की संरचना बदली, बल्कि चार दशकों में न्यायिक मिसालों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को भी समाप्त करने की कोशिश हुई। वन भूमि के गैर-वानिकी और वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना आदिवासी और वन निवासी समुदायों का सबसे मूल अधिकार है। इन संशोधनों से इस मूल अधिकार पर सबसे अधिक चोट पहुँची है।

कोयला धारक क्षेत्र में वनाधिकार एवं पेसा की अनदेखी

कोयला धारक (अर्जन और विकास) (संशोधन) विधेयक, 2024 (मसौदा) में नई धारा 13A का प्रश्ताव है। इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के समय, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान किया जाएगा। यह अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसूचियों। , ॥ एवं।।। के अनुसार तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों/आदेशों के अनुसार होगा। इस मसौदे में पेसा कानून, वन अधिकार कानून और अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के अनिवार्य पालन का कोई उल्लेख नहीं है। मसौदा सभी राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों और जनता के समक्ष टिप्पणियों के लिए अभी भी लंबित है।

खनिज रियायत अनुज्ञप्ति नियम, 1960 में संशोधन

राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे खनन योजनाओं को ब्लॉक सीमा से बाहर खनन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सके। खनन योजनाओं में मामूली परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है। ऐसे परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की अनिवार्य स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे मामूली परिवर्तनों की सूची में शामिल हैं-भूमि के प्रकार में परिवर्तन, बुनियादी अवसंरचना का स्थान परिवर्तन, उत्पादन में 50% तक की वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि का पुनः उपयोग, उपकरणों में परिवर्तन, हाई वॉल खनन, सोलर ऊर्जा के प्लांट, धुलाई अपशिष्टों का निपटान, और सामुदायिक विकास परियोजनाएँ।

पर्यावरण ऑडिट नियम

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और नामित पर्यावरण ऑडिट एजेंसी को ऑडिट प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए दिशानिर्देश और प्रारूप जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ऑडिट प्रक्रिया में वन-आश्रित समुदायों या ग्राम सभाओं की भूमिका का कोई जिक्र नहीं है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन

औषधीय उपयोग के लिए खेती की गई वनस्पतियों को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के दायरे से बाहर कर दिया गया। जैव विविधता के उत्पादकों और कृषकों, वैद्य, हकीम तथा पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधन प्राप्त करते समय, राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व सूचना देने से छूट दी गई। यह संशोधन वनाधिकार कानून की धारा 5 के तहत वन, वन्य जीव और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के ग्राम सभा के अधिकार को काम करता है। समुदायों के बौद्धिक संपदा अधिकार को भी दरकिनार करता है। इस संशोधन में वन अधिकार कानून के तहत उपलब्ध ग्राम सभाओं के वैधानिक अधिकार की अनदेखी हुई है। हालाँकि, लाभ-साझेदारी की व्यवस्था धारा 21 (2) के तहत अभी भी आवश्यक है।

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन:

माइनिंग (खनिज) नियम 2021 एवं संशोधन 2023 में केंद्र को राज्य के हश्तक्षेप के बिना खनिज ब्लॉक नीलामी का अधिकार मिला। अब खनन पट्टे का आवंटन केंद्रीकृत हो गया है। इससे ग्राम सभा की सहमति का महत्व घटा और स्थानीय स्वामित्व की धारणा कमजोर पड़ी। इस संशोधन में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान हैं-गहरे खनिजों (200 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाने वाले खनिज) के लिए खनन पट्टा या समग्र लाइसेंस धारक को सन्निहित क्षेत्र में विश्तार के लिए एकमुश्त अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान।

भारत में राज्य सरकारों के ऋणों में भारी वृद्धि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगी

प्रहलाद सबनानी

किसी भी नागरिक, वाणिज्यिक संस्थान, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए बाजार से ऋण लेना केवल तब तक ही सही हैं जब तक बाजार से लिए गए ऋण से कम से कम उस श्तर तक आय का अर्जन हो कि इस ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान इस आय से आसानी से किया जा सके। परंतु, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा बाजार से ऋण यदि अनुत्पादक कार्य के लिए लिया जा रहा है तो इस ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान करना निश्चित ही मुश्किल कार्य हो सकता है।

आज भारत के कुछ राज्यों की बजटीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन राज्यों ने बाजार से भारी मात्रा में ऋण लिया हैं एवं इस ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों यथा बिजली के बिल माफ करना, नागरिकों के खातों में सीधे राशि जमा करना, मुफ्त पानी उपलब्ध कराना, कुछ पदार्थों पर सब्सिडी उपलब्ध कराना, आदि के लिए किया जा रहा है। इन राज्यों की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि इन्हें ऋणों पर अदा किए जाने वाले ब्याज एवं किश्तों के भुगतान हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा हैं। यदि कुछ और वर्षों तक इन राज्यों की यही स्थिति बनी रही तो निश्चित ही यह राज्य दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाने वाले हैं।

हाल ही के कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा भी बाजार से ऋण लेने की राशि में वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार पर 1.74 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण बक़ाया था जो वर्ष 2025 में, लगभग दुगना होते हुए, बढ़कर 3.42 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है और वर्ष 2029 तक इसके 4.89 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद आज 4.19 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के श्तर पर पहुंच गया है। इस प्रकार, भारत सरकार का ऋण, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 80 प्रतिशत के श्तर को पार कर गया है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की निर्भरता ऋण पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिसे देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। आज केंद्र सरकार पर 200 लाख करोड़ रुपए की राशि का ऋण बक़ाया है एवं समश्त राज्य सरकारों पर 82 लाख करोड़ रूपए का ऋण बकाया है, इस प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप से 282 लाख करोड़ रुपए का ऋण बक़ाया है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 81 प्रतिशत है। एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ऋण के ऊपर विकसित की जा रही है। जबकि, भारतीय आर्थिक दर्शन ऋण पर निर्भरता को प्रोत्साहन नहीं देता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, राजा के पास कोष में आधिक्य होने का वर्णन मिलता है। राजा के पास यदि ऋण के स्थान पर कोष का आधिक्य होगा तब वह राज्य अपने नागरिकों के कल्याण पर अधिक राशि खर्च करने की स्थिति में रहेगा। अर्थात, प्राचीन भारत में राज्यों का आधिक्य का बजट रहता था, उसी स्थिति में वे राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के कार्यों को तेज गति से चलाने की स्थिति में रहते थे।

राज्य का खजाना ही यदि खाली हो तो वे किस प्रकार से राज्य के नागरिकों के लिए भलाई के कार्य कर सकते हैं। आज की स्थिति, बिलकुल विपरीत दिखाई देती है और आज कुछ राज्य बाजार से ऋण लेकर भी नागरिकों को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध करा रहें हैं बगैर यह सोचे समझे कि आगे आने वाले समय में बाजार से लिए गए ऋण का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।

आज भारत में कुछ राज्यों की स्थिति यह है कि वे अपनी कुल आय का 55 प्रतिशत भाग कर्मचारियों को वेतन, पेन्शन एवं उधार ली गई राशि पर ब्याज के भुगतान करने जैसी मदों पर खर्च कर रहे हैं। जबकि, विभिन्न राज्य अपनी आय को बढ़ा सकने की स्थिति में नहीं है।

कुछ राज्य तो वर्ष भर में जिस आय की राशि का आंकलन करते हैं उसे प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं और बजटीय आय की राशि एवं वाश्तविक आय की राशि में 11 प्रतिशत तक की कमी रहती है, जबकि इन राज्यों के खर्च नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार इन राज्यों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह असहनीय स्थिति में पहुंच गया है। आज राज्यों की कुल आय का 84 प्रतिशत भाग स्थिर मदों पर खर्च हो रहा है। प्रदेश को आगे बढ़ाने एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए कुछ राशि इन राज्यों के पास उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है।

पूंजीगत खर्चों में लगातार हो रही कमी के चलते इन राज्यों में नए अस्पतालों का निर्माण, नए रोड का निर्माण नए स्कूल हेतु भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। पंजाब में कुल आय का 76 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन एवं ऋण पर ब्याज अदा करने जैसी मदों पर खर्च हो रहा है इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 79 प्रतिशत एवं केरल में 71 प्रतिशत भाग उक्त मदों पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही, कुछ राज्यों द्वारा अपनी कुल आय का भारी भरकम हिस्सा सब्सिडी जैसी मदों पर खर्च किया जा रहा है।

जैसे, पंजाब द्वारा अपने बजटीय आय का 24 प्रतिशत भाग सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश द्वारा 15 प्रतिशत, तमिलनाडु द्वारा 12 प्रतिशत एवं राजस्थान द्वारा 13 प्रतिशत राशि सब्सिडी पर खर्च की जा रही है। पंजाब द्वारा तो अपने बजट की 100 प्रतिशत राशि (24 प्रतिशत सब्सिडी पर एवं 76 प्रतिशत राशि वेतन, पेन्शन एवं ब्याज पर खर्च की जा रही है) सामान्य मदों पर खर्च की जा रही है और पूंजीगत खर्चों के लिए शून्य राशि बचती है। विभिन्न राज्यों द्वारा पेन्शन की मद पर वर्ष 1980-81 में अपने राज्य की कुल आय का केवल 3.4 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जा रहा था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया। इसी कारण से भारत सरकार ने पेन्शन अदा करने के नियमों में परिवर्तन किया था। आज यदि पेन्शन की नीति को नहीं बदला गया होता तो इस मद पर होने वाला खर्च बढ़कर 30 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाता। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कई राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च को घटाया है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के बीच राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च में 51 प्रतिशत तक की कमी की है। दिल्ली में 38 प्रतिशत, पंजाब में 40 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 41 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 33 प्रतिशत से पूंजीगत खर्चों में कमी दर्ज हुई है। आज कई राज्य सरकारें सब्सिडी प्रदान करने की मद पर अपने खर्चों को लगातार बढ़ा रहीं हैं एवं पूंजीगत खर्चों को लगातार घटा रही हैं, जो उचित नीति नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार तो इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं शीघ्र ही डूबने के कगार पर पहुंच जाने वाली हैं। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं।

सब्सिडी, वेतन, पेन्शन एवं ब्याज जैसी मदों पर लगातार बढ़ रहे खर्चों के कारण आज 15 राज्यों का बजटीय घाटा कानूनी रूप से निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से ऊपर हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बजटीय घाटा बढ़कर 4.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 4.1 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 4.2 प्रतिशत एवं पंजाब में 3.8 प्रतिशत के खतरनाक श्तर पर पहुंच गया है।

इसी क्रम में ध्यान में आता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 5200 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसलिए चर्चा में है क्योंकि भाईदूज के अवसर पर 'लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में राशि समय पर नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद सरकार ने प्रदेश स्थापना दिवस पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऋण लेने का राश्ता चुना है। जब किसी राज्य को सामाजिक योजनाओं पर खर्च के लिए ऋण लेना पड़े तो यह स्थिति उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। मध्यप्रदेश द्वारा ऋण लेने की रफ्तार पिछले कुछ वर्षों में कुछ तेज हुई है।

मार्च 2024 तक मध्यप्रदेश राज्य पर 3.7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर 4.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जबकि, मध्यप्रदेश की आय में इस रफ्तार से वृद्धि नहीं देखी जा रही है। वित्तीथय अनुशासन की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि ब्याज भुगतान का बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल एवं पश्चिम बंगाल की राह पर कहीं मध्यप्रदेश राज्य भी तो नहीं चल पड़ा है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। **संपादक** : संजय शर्मा
फोन: 9899683800 वेबसाइट : www.khabariya.com **ई-मेल:** todayncr@gmail.com >> ncrtoday@hotmail.com
RNI-UPHIN/2009/30721

संक्षिप्त समाचार

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, ये गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है

लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारे दिलों में राष्ट्र प्रथम की भावना को दर्शाता है। भारत की आजादी के दौरान इस गीत ने सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिनके नेतृत्व में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह गीत हमारे देश की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ के लोकभवन में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

एटा में बेहद घिनौना कृत्य... शराब में मिलाकर पिलाई पेशाब, युवक संग ऐसी बर्बरता

एटा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में तमंचा दिखाकर पहले तो अपहरण किया उसके बाद शराब में पेशाब मिलकर पिलाई। इतना ही नहीं आरोपियों ने इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया। जेब में रखे रुपये निकाल और पीटा। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सकीट कीर्तिका सिंह ने बताया कि 5 नवंबर को पुष्पेंद्र ने थाना मलावन में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 2 नवंबर को रात के समय गाड़ी चलाने और रुपयों के विवाद में सोनू, छोटे व दो अन्य अज्ञात लोगों ने ट्रक से जबरन उठाकर कार में डाल लिया। पीटते हुए जेब में रखे हुए 4270 रुपये निकाल लिए और तमंचे के बल पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने थाना मलावन और रिजोर पुलिस की टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। पुलिस टीम ने जांच-पड़ताल करते हुए दो आरोपियों जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी नगला भजा और नीतेश उर्फ छोटे निवासी मंडी गेट कोतवाली नगर को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक मोबाइल 700 रुपये लूट के व अन्य 17000 रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपियों को मलावन थाना क्षेत्र में गांव हाड़ई जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है।

ईस्टर्न पेरीफेरल पर हादसा

झगड़ रहे ट्रक और पिकअप चालक को कंटेनर ने रौंदा, एक की मौत, दो गंभीर

बागपत, एजेंसी। बागपत के रटौल में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर सरफाबाद गांव के समीप रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क किनारे आपस में झगड़ रहे पिकअप चालक और ट्रक चालक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, कासगंज जनपद के थाना सहावर के दमपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय अंशु पुत्र उदयवीर पिकअप लेकर हरियाणा से गाजियाबाद की ओर जा रहा था। सरफाबाद के पास नवोदय विद्यालय के समीप उसकी गाड़ी आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। यह ट्रक राजेंद्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी मिलयानी, जिला भिवानी (हरियाणा) चला रहा था और उसके साथ उसका भाई राजू भी सवार था। टक्कर के बाद दोनों चालक सड़क किनारे उतरकर आपस में झगड़ रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ने सभी को कुचल दिया और मौके से निकल गया। हादसे में अंशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेंद्र और राजू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही हाईवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा।

हादसे में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत

रामनगर, एजेंसी। रामपुर थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव के पास हाईवे पर मंगलवार को सड़क पार कर रहे बालक को बचाने में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान बृहस्पतिवार की सुबह मौत हो गई। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के दौड़ी गांव निवासी सभाजीत यादव (60) किसी कार्य से मंगलवार की दोपहर रामपुर बाजार की तरफ जा रहे थे। जमालापुर बाजार के आगे जोगापुर गांव में पहुंचे थे, तभी एक 10 वर्षीय बच्चा सड़क पार करने लगा। बच्चे को टक्कर से बचाने के लिए सभाजीत ने अपनी बाइक को मोड़ने का प्रयास किया। इस बीच बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

यूपी सरकार के मंत्री की दो टूक...

सफाई व्यवस्था में बेवजह हस्तक्षेप न करें पार्षद

लखनऊ, एजेंसी। महापौर और नगर आयुक्त के बीच अधिकारों को लेकर चल रही तनातनी का असर जिले के प्रभारी मंत्री की बैठक में भी रहा। बैठक में मंत्री की ओर से वही मुद्दे अफसरों के सामने उठाए गए, जिनको लेकर महापौर नगर आयुक्त को घेरती रही हैं।

इसके साथ ही सफाई के मुद्दे पर बंद लफ्जों में मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी कह दिया कि यह काम प्रशासनिक है। इसमें पार्षदों और राजनीतिक व्यक्तियों को बेवजह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मंत्री के इस बयान से माना जा रहा है कि उन्होंने दोनों पक्षों को अपनी हद में रहने की ताकीद की।

स्मार्ट सिटी ऑफिस में शाम चार बजे जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम के कामकाज की समीक्षा की। इसमें महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार के अलावा सभी अपर नगर आयुक्त और जोनल अधिकारी शामिल हुए। यहां नगर निगम की ओर से सभी विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया गया। इस पर मंत्री कई निर्देश दिए और काम में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक के दौरान महापौर ने अफसरों के अधिकारों पर कोई टिप्पणी नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि प्रभारी मंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उन पर अमल किया जाएगा। मंत्री ने भी कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्री ने बैठक में नगर निगम की आय बढ़ाने, खर्च में कमी करने, स्वच्छता प्रोत्साहन समिति पहले की तरह बनाने और सरकारी जमीनों को सुरक्षित करने पर विशेष जोर दिया। अंत में उन्होंने कहा कि वह एक महीने बाद फिर से समीक्षा करेंगे।

मंत्री ने नगर निगम अफसरों को दिए ये निर्देश

- सड़कों की नियमित रूप से सुबह और रात में सफाई की जाए। सभी जोनल अधिकारी सफाई की निगरानी प्रतिदिन करें। शिकायतों निस्तारण समय से हो।
- गृहकर, जलकर एवं अन्य करों को जमा करने में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। भुगतान के लिए सरल और सुलभ विकल्प उपलब्ध कराए जाएं।
- निर्धारित पार्किंग स्थलों को चिह्नित कर सुचारू रूप से संचालित किया जाए। सड़कों पर अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई हो।
- नगर निगम की सभी जमीनों की वीडियोग्राफी प्रवर्तन दस्ते के सहयोग से कराई जाए। इससे भविष्य में भूमि पर अवैध कब्जे या विवादों से बचाव होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि शहर की धरोहर है। इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा।
- शहर के प्रत्येक मकान का एक नंबर निर्धारित होना चाहिए। यह नंबर मैप पर भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। इससे पते की पहचान में सरलता होगी। डाक-डिलीवरी, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में सहजता बढ़ेगी।
- स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का गठन वार्ड स्तर पर किया जाए।
- किराये की संपत्तियों से किराया वसूलने के लिए एक निश्चित फार्मूला तैयार किया जाए। 31 दिसंबर से पहले कमेटी बनाकर आय में सुधार किया जाए।
- स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम अलग से अपना बंच वायर डाले। इसके लिए शासन से बजट दिलाया जाएगा।
- प्रत्येक नाली की कम से कम महीने में एक बार सफाई निश्चित रूप से कराई जाए।

जोन पांच व आठ में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज कार्यों को तेज किया जाए

- सभी जोनल अधिकारी हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करें और नगर आयुक्त महीने में एक बार व्यापक समीक्षा अवश्य करें, जिससे कार्यों की गति और गुणवत्ता बनी रहे।
- म्यूनिसिपल बांड से जुटाए गए रुपयों से आवासीय योजना अहाना ग्रींस के खाली फ्लैटों को बेचने की कार्रवाई तेज की जाए।
- अभियंत्रण विभाग हर जोन में एक टीम बनाए जो शहर में निकलकर सड़कों और गलियों का निरीक्षण करे। यदि कहीं गड्ढा हो तो उसे तत्काल भरवाया जाए जिससे वह बड़ा न हो।

यूपी में एक और एनकाउंटर... 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर

वाराणसी, एजेंसी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में एक और पशु तस्कर को मार गिराया है। यह मुठभेड़ आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना इलाके में हुई है। जोकहरा गांव में छोटी सरयू नदी के पास लखनऊ एसटीएफ, आजमगढ़ स्वाट टीम और सिधारी पुलिस की टीम से पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई।

इस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामिया पशु तस्कर गोली लगने से ढेर हो गया। जबकि उसके तीन साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, रौनापार थाना के जोकहरा गांव के पास छोटी सरयू नदी के रास्ते पर बृहस्पतिवार की देर रात लखनऊ एसटीएफ, आजमगढ़ की स्वाट टीम और थाना सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर बदमाशों तस्करों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि तीन अन्य मौके से फरार हो गए।

67 से अधिक मुकदमे दर्ज मारे गए बदमाश वाकिफ पर गौ तस्करी, चोरी, हत्या और लूट के आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर व जौनपुर समेत कई जिलों में 67 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह 50 हजार रुपये का इनामी था। पुलिस ने मौके से असलहा व कारतूस बरामद किए हैं और फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा, लगाए समिति कर्मचारियों पर मनमानी करने के आरोप

हाथरस, एजेंसी। सासनी बस स्टैंड स्थित सहकारी समिति पर 6 नवंबर को डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ी। किसानों ने सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन खाद नहीं मिल सकी। किसानों ने हंगामा भी किया और समिति कर्मचारियों पर खाद वितरण में मनमानी के आरोप लगाए। किसानों ने बताया कि वे सुबह जल्दी आकर कतार में लग गए, लेकिन शाम तक उन्हें खाद नहीं मिली। समिति के सचिव किसानों को यह कहकर टहलाते रहते हैं कि वे उनकी समिति के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें यहां से खाद नहीं मिल सकती। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी आलू की बुवाई नहीं हो पा रही। अगर बुवाई ज्यादा लेट हुई तो आलू की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। वे सुबह से घर के सभी कामकाज छोड़कर समिति पर आकर कतार में लगते हैं और शाम को उन्हें खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। सचिव महाराज सिंह का कहना है कि सभी को नियमानुसार खाद दिया जा रहा है। किसान जो आरोप लगा रहे हैं, वे गलत हैं।

93 करोड़ का गंगा बैराज मार्ग चौड़ीकरण अटका

मात्र 100 मीटर के अतिक्रमण ने रोका काम, 15 नवंबर है डेडलाइन

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में करीब 93 करोड़ से हो रहा गंगा बैराज मार्ग का चौड़ीकरण मात्र 100 मीटर के दायरे में अतिक्रमण की वजह से अटक गया है। पीडब्ल्यूडी की चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने जमीन खाली नहीं की है। कार्य की डेडलाइन पूरी होने में नौ दिन ही बचे हैं। मंधना से गंगा बैराज, उन्नाव होते हुए मोहनलालगंज लखनऊ तक 104 किलोमीटर लंबे मार्ग को दो साल पहले राज्य मार्ग घोषित किया गया था।

इस मार्ग पर लगातार बढ़ते वाहनों के लोड के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड-दो ने डेढ़ साल पहले मंधना से गंगा बैराज होते हुए उन्नाव जिले की सीमा तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण कार्य शुरू कराया। 93 करोड़ रुपये से इस रोड को चार लेन करने के साथ ही बीच में 1.20 मीटर चौड़ा डिवाइडर और दोनों तरफ इंटरलाकिंग टाइल्स से फुटपाथ बनाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई जा रही हैं।

अभी तक चौड़ीकरण कार्य शुरू नहीं हो पाया- कार्य पूरा करने की डेडलाइन 15 नवंबर है। जब इस सड़क की पड़ताल की, तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव से गंगा बैराज, सिंहपुर चौराहा होते हुए मंधना में कानपुर-अलीगढ़ राष्ट्रीय मार्ग से पहले 200 मीटर दूर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य हो गया है। डिवाइडर भी बन गया है। इस 200 मीटर के हिस्से में से लगभग 100 मीटर हिस्से में चौड़ीकरण के दायरे में मकानों, दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण आड़े आ रहे हैं। इस वजह से वहां अभी तक चौड़ीकरण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

विभाग ने ठेकेदार को दी चेतावनी

विभाग से जानकारी करने पर पता चला कि अतिक्रमणकारियों को छह महीने पहले चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। डेढ़ महीने पहले दोबारा अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया तो सभी ने दीपावली तक दुकानें पूर्ववत लगाने की मोहलत मांगी और इसके बाद खुद अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी ने उन्हें दीपोत्सव तक की मोहलत दे दी, लेकिन त्योहार बीतने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उधर, विभाग ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए तय समय में कार्य पूरा करने के लिए कहा है।

श्रीनगर पुलिस का छापा

सहारनपुर के निजी अस्पताल से चिकित्सक को उठाया

जैश-ए-मोहम्मद के लगाए थे पोस्टर

सहारनपुर, एजेंसी। सहारनपुर जनपद में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर पुलिस ने देर रात सहारनपुर में पहुंची। यहां से एक निजी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ. अदिल अहमद को हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। आरोप है कि चिकित्सक श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने में शामिल है। पिछले महीने ही चिकित्सक ने निकाह किया था। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी डॉ. अदिल अहमद अंबाला रोड स्थित एक बड़े निजी अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में तैनात है। कुछ दिन पहले श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। इनमें आतंकी संगठन के समर्थन में मेसेज लिखे थे। इस घटना के बाद श्रीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें डॉ. अदिल का नाम सामने आया। कुछ दिन पहले श्रीनगर पुलिस ने डॉ. अदिल के घर अनंतनाग पहुंची थी। वहां से पता चला था कि डॉ. अदिल सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में तैनात है। बृहस्पतिवार देर शाम श्रीनगर पुलिस शहर में पहुंची। यहां एसएसपी से मिली।

दिल्ली रोड पर एक निजी अस्पताल में रह चुका चिकित्सक

डॉ. अदिल दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भी कार्यरत रह चुका है। इसके बाद अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में नौकरी कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाल ही में चिकित्सक ने एक महिला चिकित्सक से निकाह किया था। वहीं, अब स्थानीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जम्मू-कश्मीर से आने वाले लोगों की जांच शुरू की जा रही है।

दुकान खाली कराने को लेकर बवाल

मालिक और किरायेदार में मारपीट महिलाओं से छेड़खानी का आरोप

आगरा, एजेंसी। आगरा के शिवाजी मार्केट में दुकान खाली करने के विवाद में मालिक और दुकानदार के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। हंगामा होने पर पुलिस पहुंच गई। मामले में दोनों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि दुकान खाली नहीं करने पर मालिक से विवाद हुआ था। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नाला काजीपाड़ा, रकाबगंज निवासी राहुल कुमार पिप्पल की शिवाजी मार्केट में जूते की दुकान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार शाम तकरीबन 6 बजे रकाबगंज क्षेत्र के परिवार के लोगों और महिलाओं ने रंजिश में दुकान पर हमला बोल दिया। लाठी-डंडे हाथों में लिए हुए सभी लोगों ने गालीगलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

पिता राजेश कुमार पिप्पल व मां लक्ष्मी देवी बचाने आईं तो उन्हें भी पीटा। पड़ोस के लोग आए तो आरोपी धमकी देकर भाग गए। दूसरे पक्ष की युवती ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में दुकान है। दुकानदार और उसका भाई उनका और उसकी बहन का पीछा करते हैं। 4 नवंबर की शाम को घर के बाहर खड़ी बहन को दुकानदार ने आकर पकड़ लिया। विरोध पर कपड़े फाड़ दिए और गला दबाने का प्रयास किया। परिवार की अन्य महिलाएं बचाने आईं तो उनको भी पीटा। आरोपी का परिवार भी एकजुट हो गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों में दुकान का विवाद चल रहा है। राहुल कुमार दुकान में किरायेदार हैं। वहीं दूसरा पक्ष मालिक हैं। वह दुकान खाली कराना चाहते हैं। इस पर विवाद चल रहा है। दोनों ओर की ओर से केस दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।

पीएमओ तक पहुंचा बिजली के निजीकरण का विवाद

उपभोक्ता परिषद ने खाामियां गिनाते हुए भेजा प्रस्ताव

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश में निजीकरण व सुधार के नाम पर किए जा रहे नए प्रयोगों से उपभोक्ताओं की समस्याएं घटने के बजाय बढ़ने लगी हैं। यह आरोप लगाते हुए राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र भेजा है। सुधार के सुझाव भी दिए हैं। इसे सात नवंबर को पीएमओ में होने वाली ऊर्जा सुधार बैठक में शामिल करने की मांग की है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1934 में कहा था कि बिजली हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहनी चाहिए। सस्ती नहीं बल्कि बहुत सस्ती होनी चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान निर्माता के बताए हुए रास्ते पर चलें। देश में बिजली सस्ती करने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई विद्युत वितरण सुधार योजना का विरोध किया गया है। मांग की गई है कि इसे उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए। परिषद ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह योजना सुधार नहीं, बल्कि एक और वित्तीय बेलआउट (ऋण पुनर्गठन) है, जिसका पहला शर्त निजीकरण को बढ़ावा देना एवं बिजली दरों में वृद्धि करना है, जो पूर्णतः उपभोक्ता विरोधी कदम हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा प्रबंध पहले से ही निजीकरण का पक्षधर है। इसलिए वह निजीकरण के पक्ष में ही जानकारी देगा। वर्मा ने कहा कि हर पांच वर्ष में नई-नई योजनाएं जैसे - एपीडीआरपी, आर-एपीडीआरपी, एफआरपी, उदय, आरडीएसएस आदि लाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक सुधार जैसे वितरण दक्षता में सुधार, हानि नियंत्रण, समय पर सब्सिडी भुगतान, और जवाबदेही तय करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। इस वजह से भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

हॉन्गकॉन्ग सिक्सेज 2025:

भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराया, रॉबिन उथप्पा बने प्लेयर ऑफ द मैच

नई दिल्ली, एजेंसी। हॉन्गकॉन्ग सिक्सेज 2025 के ग्रुप सी के एक मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ हुआ। ये मैच पूरा नहीं खेला जा सका और अंत में डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर भारत को विजेता घोषित कर दिया गया। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2 रन से हराने में सफलता हासिल की। भारतीय ओपनर रॉबिन उथप्पा को उनकी तेज पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इस मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 4 विकेट पर 86 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 87 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान की टीम ने दूसरी पारी में 3 ओवर में एक विकेट पर 41 रन बना लिए थे तभी जोरदार बारिश आ गई और फिर मैच नहीं हो सका। अंत में भारत को विजयी घोषित कर दिया गया। इस टूर्नामेंट में भारत ने जीत केसाथ आगाज किया।

भारत की पारी, उथप्पा ने बनाए सबसे ज्यादा रन

पाकिस्तान के खिलाफ पारी की शुरुआत करने रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली आए थे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी हुई और फिर उथप्पा आउट हो गए। उथप्पा ने 11 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौकों के साथ 28 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 254.55 का रहा। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए स्टुअर्ट बिन्नी कुछ खास नहीं कर पाए और वो 2 गेंदों पर एक चौके की मदद से 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथे नंबर पर बैटिंग करने खुद कप्तान दिनेश कार्तिक आए जिन्होंने 6 गेंदों पर एक छक्का और 2 चौकों के साथ नाबाद 17 रन की पारी खेली और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 283.33का रहा। भारत के लिए भरत चिपली ने 13 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 24 रन बनाए जबकि अभिमन्यु मिथुन ने 5 गेंदों पर एक चौके के साथ 6 रन बनाए और रन आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से इस मैच में मोहम्मद शहजाद ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए जबकि अब्दुल समद को एक सफलता हासिल हुई।

पाकिस्तान की पारी

पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 3 ओवर में एक विकेट पर 41 रन बनाए और बारिश की वजह से बचे हुए 3 ओवर का खेल नहीं हो पाया। पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत ख्वाजा नफे और माज सदाकत ने की थी। माज 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर स्टुअर्ट बिन्नी का शिकार हुए जबकि ख्वाजा नफे 9 गेंदों पर 2 छक्के और एक चौके की मदद से 18 रन बनाकर नाबाद रहे। अब्दुल समद 6 गेंदों पर एक छक्का और 2 चौकों के साथ 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

दादा का सपना पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर ने ली भारतीय नागरिकता

बेंगलुरु, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉलर रायन विलियम्स ने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है, जिससे वह अब भारतीय नेशनल फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हो गए हैं। बेंगलुरु एफसी के कप्तान 32 वर्षीय विलियम्स ने अपने दिवंगत दादा, जो मुंबई के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यह भावनात्मक कदम उठाया है।

घर वापसी और विरासत

विलियम्स ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़कर भारतीय पासपोर्ट लिया है। उनके लिए यह घर वापसी जैसा है, क्योंकि उनकी मां का जन्म भारत में हुआ था और उनके दादा, लिंकन एरिक ग्रोस्टेट, 1956 में संतोष ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। विलियम्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि उनके दादाजी की इच्छा थी कि वह भारत में खेलें।

इंडिया-ऑस्ट्रेलियाः

ब्रिस्बेन में निर्णायक टी20 मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज़ का अंतिम और पाँचवाँ मुकाबला शनिवार को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। भारत 2-1 की बढ़त के साथ पहले ही सीरीज़ अपने पक्ष में कर चुका है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इस दौरे का समापन शानदार जीत से करना चाहेगी। टीम का फोकस अपनी बल्लेबाज़ी कमजोरियों को सुधारने और लय में लौटने पर रहेगा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश स्पिनरों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर प्रतिष्ठा बचाने की होगी।

भारत का लक्ष्य – बल्लेबाजी में सुधार और दमदार समापनः भारत इस टी20 सीरीज़ में 2-1 से आगे है और 17 साल से ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज़ न हारने की परंपरा को कायम रखा है। अब टीम का लक्ष्य शानदार जीत के साथ इस दौरे को समाप्त करना है। पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाज़ों ने अच्छी शुरुआत के बावजूद बीच ओवरों में तेज़ी से विकेट गंवाए, जिससे टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुँच पाई। इस बार कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल पर जिम्मेदारी होगी कि वे ठोस शुरुआत को बड़ी पारी में बदलें।

शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीदः शुभमन गिल पिछले सात मैचों में अर्धशतक नहीं बना पाए हैं। हालांकि पिछले मैच में उनकी 46 रनों की पारी ने उम्मीदें जगाई थीं। वे एक बार फिर टीम प्रबंधन का भरोसा जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। सूर्यकुमार यादव ने पूरी सीरीज़ में स्थिर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भी बड़ी पारी खेलने में संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले वे इस मैच में आक्रामक और नेतृत्वकारी पारी खेलकर उदाहरण पेश करना चाहेंगे।

मध्यक्रम और निचले क्रम पर भी निगाहेंः तिलक वर्मा और जितेश शर्मा के लिए यह मैच अहम होगा। तिलक हालिया मैचों में लगातार असफल रहे हैं, जबकि जितेश पर संजू सैमसन से बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में तेज़ अर्धशतक लगाकर शीर्ष क्रम को मजबूती दी है। वहीं, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर टीम की गहराई को बढ़ा रहे हैं। पिछले मैच में अक्षर ने मात्र 11 गेंदों पर 21 रन बनाए थे, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुए।

गेंदबाजी में स्थिरता और स्पिनरों का जलवाः गेंदबाज़ी विभाग में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी एक बार फिर टीम की ताकत बनी हुई है। अर्शदीप ने पिछले मैच में चार विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। वाशिंगटन ने पिछले मैच में तीन विकेट झटके, जबकि दुबे ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती – स्पिन और स्थिरताः ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय स्पिनरों के सामने संघर्ष कर रही है। ट्रैविस हेड की अनुपस्थिति ने टीम को कमजोर किया है, जबकि मिशेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड पर अब तक पूरी जिम्मेदारी रही है।

टीमेंः

भारतः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), जोश फिलिप (विकेट कीपर), मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट कुहनेमन, एडम ज़म्पा, महली बियर्डमैन, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मार्कस स्टोइनिस।

पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया

नई दिल्ली, एजेंसी। देश भर के 60 से ज्यादा सक्षम तीरंदाजों के बीच समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करते हुए जम्मू-कश्मीर की 18 वर्षीय तीरंदाज शीतल सोनीपत में हुए चार दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रायल में तीसरे स्थान पर रहीं। जन्म से ही भुजाहीन पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने गुरुवार को एक और उपलब्धि हासिल करते हुए जेद्दा में होने वाले आगामी एशिया कप चरण तीन के लिए भारत की सक्षम जूनियर टीम में जगह बनाई। विश्व कंपाउंड चैंपियन शीतल के लिए एक सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल होना एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है।

भारत की एशिया कप सक्षम टीम में जगह बनाई

'मेरा एक छोटा सा सपना था...'

शीतल ने टीम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, 'जब मैंने प्रतिस्पर्धा शुरू की थी तो मेरा एक छोटा सा सपना एक दिन सक्षम तीरंदाजों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। शुरुआत में मैं इसमें सफल नहीं हो पाई, लेकिन मैं हर असफलता से सीखते हुए आगे बढ़ती रही। आज वह सपना एक कदम और करीब आ गया है।'

क्वालिफिकेशन में 703 अंक हासिल किए

देश भर के 60 से ज्यादा सक्षम तीरंदाजों के बीच समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करते हुए जम्मू-कश्मीर की 18 वर्षीय तीरंदाज शीतल सोनीपत में हुए चार दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रायल में तीसरे स्थान पर रहीं। शीतल ने क्वालिफिकेशन दौर में 703 अंक हासिल किए (पहले दौर में 352 और दूसरे दौर में 351) जो शीर्ष क्वालीफायर तेजल साल्वे के कुल अंक के बराबर स्कोर था।

इस बार मिलेगी ट्रॉफी ?

PAK से तकरार, एक और एशिया कप के लिए टीम इंडिया तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप टी-20 का खिताब जीते एक महीना बीत चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विजेता ट्रॉफी अब तक भारतीय टीम के पास नहीं पहुंची. न कोई ट्रॉफी प्रेजेंटेशन, न कोई समापन. यह जीत अधूरी-सी लगती है. और अब जब बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार एशिया कप में भागीदारी की पुष्टि कर दी है, तो कहानी का नया अध्याय शुरू हो गया है.

पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर से लौटने वाली है, मगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की कार्यशैली पर सवाल अब भी जस के तस हैं. एशिया कप दरअसल अपनी सबसे अहम घड़ी 'ट्रॉफी मोमेंट' तक पहुंच ही नहीं पाया..यह एक ऐसा अभियान था जो भारत के लिए स्पष्ट और योग्य जीत के साथ खत्म होना चाहिए था, लेकिन यह बयानों, पलट बयानों और कूटनीतिक उलझनों में फंस गया. फिर भी, बीसीसीआई ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और टीम को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, एक और टूर्नामेंट में... वह भी पाकिस्तान की मौजूदगी वाले. इस बार यह फैसला महज एक क्रिकेटीय सिलसिला नहीं लगता, बल्कि भारत का संयम, नियंत्रण और आत्मविश्वास जताने का संकेत लगता है.

हाल ही में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान से तीन बार मुकाबला किया- ग्रुप स्टेज, सुपर-फोर और फाइनल में. मैदान पर मुकाबला तीखा था, लेकिन क्रिकेट के इर्द-गिर्द राजनीतिक रंग और भावनात्मक गर्माहट ज्यादा दिखाई दी. सबसे चर्चित क्षण वह था जब एसीसी चेयरमैन और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया. यह कदम न सिर्फ माहौल बिगाड़ गया, बल्कि सम्मान, पारदर्शिता और मंशा पर भी सवाल उठ गए. आईसीसी को दखल देना पड़ा.

दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा, चेतावनी दी गई और डिमेरिट पॉइंट दिए गए. पर इन सजाओं से भी असल मुद्दा नहीं सुलझा. ट्रॉफी अब भी एसीसी के पास है- ना लौटाई गई, ना सौंपी गई.

गुजरात ने लॉरा और यूपी ने दीप्ति को किया रिलीज, डब्ल्यूपीएल नीलामी से पहले ये खिलाड़ी हुए रिटेन

नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात जायंट्स ने लॉरा वुलफार्ट को रिटेन न करने का बड़ा फैसला लिया है क्योंकि सभी 5 टीमों ने डब्ल्यूपीएल नीलामी से पहले अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने की पुष्टि कर दी है। वुलफार्ट हाल ही में संपन्न हुए एकदिवसीय विश्व कप में शीर्ष स्कोरर रहीं और दक्षिण अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन नियमों के अनुसार केवल दो विदेशी खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता है, इसलिए जायंट्स ने बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को चुना। रिपोर्ट के अनुसार वुलफार्ट के अलावा, एक और बड़ा नाम जिसे रिटेन नहीं किया गया है, वह हैं भारत की शीर्ष ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा।

विश्व कप विजेता ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। दीप्ति ने 2024 में डब्ल्यूपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी जीता था। उम्मीद के मुताबिक, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स जैसी अन्य बड़ी भारतीय स्टार खिलाड़ियों को उनकी संबंधित टीमों ने रिटेन किया है।

मंधाना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट

दुबई, एजेंसी। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली स्मृति मंधाना को ढ्ढष्टष्ट के बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया है। 29 साल की मंधाना ने 2 नवंबर को समाप्त हुए टूर्नामेंट में 434 रन बनाए थे। उनके इस प्रदर्शन की मदद से भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराते हुए पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी।

अक्टूबर महीने के नॉमिनेशन में भारतीय उपकप्तान मंधाना के अलावा, साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर भी शामिल हैं। मंधाना ने अहम मौकों पर रन बनाए मंधाना ने टॉप ऑर्डर में भारतीय बैटिंग को लीड किया। उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रतिका रावल के साथ कई ओपनिंग पार्टनरशिप की। मंधाना ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन की और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 88 रन की आक्रामक पारी खेली। हालांकि, इन दोनों मैचों में भारती टीम हार गई।

मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो के मैच में 109 रन की पारी खेली। उन्होंने प्रतिका के साथ 212 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप की। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 45 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत कराई और शेफाली वर्मा के साथ शतकीय साझेदारी निभाई।

टीम में जगह न मिलने का पछतावा नहींः सुनील छेत्री

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने कहा है कि एशियाई कप क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम के संभावितों में शामिल न होने का उन्हें कोई पछतावा नहीं है। छेत्री ने कहा है कि मैं फुटबॉल में इतने लंबे समय से हूं कि मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है। मुझे इस बात का मलाल है कि भारत 2027 एशियाई कप फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका। हम ऐसी टीम नहीं हैं जो बस आकर जीत जाए। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, गति चाहिए, और चीजें हमारे अनुकूल होनी चाहिए।

मैं यह नहीं कह रहा कि इसीलिए हम क्वालीफाई नहीं कर पाए, लेकिन इससे मदद मिलती। भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील ने बुधवार को संभावित 23 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। इसमें पूर्व कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री का नाम नहीं था। सुनील छेत्री ने मार्च 2025 में संन्यास से वापसी करते हुए एएफसी एशियाई कप 2027 क्वालीफायर खेलने की इच्छा जाहिर की थी। उनका नाम फीफा अंतर्राष्ट्रीय विंडो के 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया था.

अवनि लेखरा : बचपन में हादसे ने बदली जिंदगी, फिर पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनकर खुद बनाई अपनी तकदीर

नई दिल्ली, एजेंसी। पैरालंपिक गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वालीं भारतीय पैरा निशानेबाज अवनि लेखरा ने देश का मान बढ़ाया है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बावजूद अवनि ने दृढ़ संकल्प और मेहनत से विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। 8 नवंबर 2001 को जयपुर (राजस्थान) में जन्मीं अवनि को बचपन से ही काफी संघर्ष करना पड़ा। जब वह महज 11 साल की थीं, तो एक दुर्घटना के चलते कमर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इस हादसे ने अवनि की जिंदगी बदल दी। अब उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता था। इस हादसे का अवनि पर गहरा प्रभाव पड़ा। हल्का सामान उठाना भी उनके लिए मुश्किल था, लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं

मानी। पिता का मानना था कि अगर अवनि को किसी खेल से जोड़ा जाए, तो उनकी मायूसी दूर हो सकती है। उन्होंने बेटी को शूटिंग शुरू करने के लिए कहा। इस हादसे के करीब 3 साल बाद अवनि शूटिंग में अपना करियर बनाने की ठान चुकी थीं। वह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा से काफी प्रेरित थीं। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में अवनि ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल एसएच 1 इवेंट के फाइनल में 249.6 के स्कोर के साथ गोल्ड जीता। वह पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। इसी पैरालंपिक में उन्होंने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन एसएच 1 में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। यह पैरालंपिक कोरोना महामारी के चलते साल 2021 में हुआ था।

फिडे विश्व कप: विदित ने फॉस्टिनो ओरो को हराया, प्रणव और प्रणेश ने तीसरे राउंड में जगह बनाई

पणजी, एजेंसी। ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना के कम उम्र के खिलाड़ी फॉस्टिनो ओरो के खिलाफ जीत हासिल की।

प्रणव वी और प्रणेश एम ने भी विश्व कप के तीसरे मैच में दौर में जगह बना ली है। 12 साल के ओरो ने विदित गुजराती पर दो क्लासिकल गेम्स में दबाव बनाया था। लेकिन, आखिरकार विदित का अनुभव उनके काम आया और काले मोहरों से खेलते हुए उन्होंने दूसरे रैपिड गेम को 52 चालों में जीता। जीत के

बाद विदित गुजराती ने फॉस्टिनो ओरो की तारीफ करते हुए कहा, 'यह मैच आसान नहीं था। युवा खिलाड़ी शतरंज बहुत अलग तरीके से खेलते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर के साथ बड़े हुए हैं। उनके पास पुरानी पीढ़ी से ज्यादा अनुभव है। 12 साल का ओरो करिश्माई है।

उसके जैसा खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। उसके खिलाफ जीत दर्ज करते हुए अगले राउंड में जगह बनाना अच्छा लग रहा है। विदित अगले राउंड में अमेरिका के सैम शैंकलैंड से भिड़ेंगे। प्रणव ने नॉर्वे के आर्यन तारी के खिलाफ पहले रैपिड गेम को 44 चालों में जीत लिया। यह रूक-पॉन एंडिंग था। दूसरे गेम में काले मोहरों से उन्होंने नॉर्वेजियन खिलाड़ी से ड्रॉ खेला और आगे बढ़ गए। अगले राउंड में प्रणव लिथुआनिया के टिटास स्ट्रेमाविसियस से खेलेंगे। जीत के बाद प्रणव ने कहा कि मैंने पहले के मुकाबलों के बारे में न सोचते हुए सिर्फ अपना गेम खेला। मेरी तैयारी काम आई और मैं जीतने में सफल रहा।